राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार 20 नवंबर 2026 वर्ष-9,अंक-285 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ट्रम्प-जिनपिंग और पुतिन की पहली बार एक साथ मीटिंग

जिनपिंग बोले- परमाणु हथियार इंसान के सिर पर लटकती तलवार, इन्हें खत्म करें



शेनझेन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के शेनझेन शहर में ऐतिहासिक बैठक की। यह पहली बार हुआ जब तीनों नेताओं ने एक साथ त्रिपक्षीय बैठक की।

मीटिंग में सबसे पहले परमाणु हथियारों के खतरों पर बातचीत हुई। जिनपिंग ने परमाणु हथियारों को इंसानियत के सिर पर लटकती तलवार बताया। उन्होंने कहा कि इन्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए।

पुतिन ने कहा कि रूस, चीन और अमेरिका तीनों ने दूसरे विश्व युद्ध में जीत हासिल की थी। इसलिए दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इन तीनों देशों की है। ट्रम्प ने कहा कि वे इस बात से बेहद खुश हैं कि तीनों देशों के बीच पहली बार त्रिपक्षीय बैठक हो रही है। यह इतिहास रचने जैसा है।

बैठक करीब 80 मिनट चली

चीन के सरकारी चैनल के मुताबिक, जिनपिंग, ट्रम्प और पुतिन के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक



खत्म होने के बाद ट्रम्प का काफिला किलिन विला से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। यह बैठक करीब 80 मिनट चली।

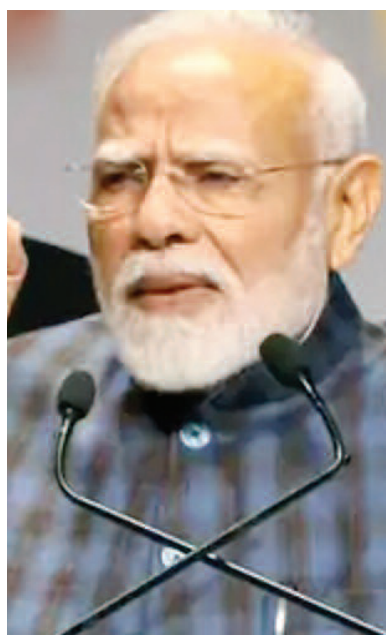
मोदी बोले- किसानों और कारोबारियों को गाली देने से देश नहीं बढ़ता

हमने 12 साल में इकोनॉमी बदली

राहुल ने कहा था- भारत आर्थिक संकट की ओर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि किसानों और कारोबारियों को गाली देने से देश आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में भारत की इकोनॉमी बदली है और 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पीएम का यह बयान राहुल गांधी के आरोपों के एक दिन बाद आया है। राहुल ने बुधवार को न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी खामियां हैं।

50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले-पीएम मोदी ने कहा कि 1970 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तब भारत की आबादी करीब 50 करोड़ थी। लेकिन अर्थव्यवस्था पिछले 12-13 साल में बदली है। आज 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। पीएम ने कहा कि कुछ कंपनियां विदेशों के लिए बेहतर और भारत के लिए कम गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाती हैं। इस सोच को बदलना होगा।



ग्लोबल मार्केट के अवसरों का फायदा उठाएं

प्रधानमंत्री ने कारोबारियों से घरेलू बाजार तक सीमित न रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कंपनियों को दूसरे देशों की जरूरतों और ग्राहकों की पसंद समझकर उत्पाद तैयार करने चाहिए। मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म एक्सप्रेस के जरिए लगातार सुधार कर रही है। उन्होंने कारोबारियों से बिना झिझक अपनी समस्याएं और सुधारों से जुड़े सुझाव देने को कहा। सरकार उनके साथ खड़ी है। पीएम ने कहा कि कंपनियों को ऐसे उत्पाद बनाने चाहिए, जो ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक हों और इस्तेमाल में आसान हों। इसके लिए बेहतर रिसर्च और नई तकनीक अपनाना जरूरी है।



सोना 1.30 लाख के नीचे आज 1,179 सस्ता हुआ

7 दिन में दाम 12 हजार गिरे, हफ्तेभर में चांदी 24 हजार सस्ती

नई दिल्ली, एजेंसी। सोने-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। सोना पिछले 7 कारोबारी दिनों में करीब 12 हजार रुपए और चांदी करीब 24 हजार रुपए सस्ती हो चुकी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, गुरुवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,179 रुपए घटकर 1.30 लाख रुपए से नीचे आ गई। वहीं, एक किलो चांदी का भाव 2,158 रुपए गिरकर 1.62 लाख रुपए रह गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत होने और बड़े निवेशकों के ऊंची कीमतों पर सोना-चांदी बेचने से इनके दाम गिर रहे हैं।

रिकॉर्ड हाई से से 2.18 लाख रुपए गिरी चांदी

इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए थी, जो 29 जनवरी को 3.80



लाख रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। तब से अब तक चांदी 2.18 लाख रुपए यानी करीब 130% सस्ती हो गई है। वहीं, 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1.33 लाख रुपए था, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1.76 लाख रुपए के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। तब से अब तक सोना 46 हजार रुपए यानी करीब 35% सस्ता हो चुका है।

राहुल अमेरिका में बोले-

2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था..लेकिन चुनाव का कभी बायकॉट नहीं करेंगे, ऐसा करते ही लोकतंत्र खत्म हो जाएगा

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव वैध नहीं था। इसमें कई फर्जी मतदाता थे। उन्होंने दावा किया कि एक ब्राजीलियाई महिला, जो कभी भारत नहीं आई, उसने एक विधानसभा चुनाव में 23 बार वोट डाला। राहुल से पूछा गया कि चुनाव में गड़बड़ी के बावजूद विपक्ष उनका बायकॉट क्यों नहीं करता? इस पर उन्होंने कहा, 'भारतीय लोकतंत्र हमारे लिए पवित्र है। अगर हमने चुनावों का बायकॉट करने का फैसला किया, तो उसी पल भारतीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम लोकतंत्र को खत्म नहीं करना चाहते। हमारी स्ट्रैटजी है कि हम लड़ें और भारत के लोगों को बताएं कि देश में क्या चल रहा है।' राहुल गांधी ने यह बात गुरुवार को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के साथ हुए संवाद के दौरान कही।

बहिष्कार का कदम नहीं उठा रहे...

राहुल ने कहा कि हम जानबूझकर चुनावी बहिष्कार का कदम नहीं उठा रहे हैं और हमें भरोसा है। चुनाव आयोग खुद अब अंदर से हमें जानकारी दे रहा है। इसलिए यह ढांचा कब ढहेगा, यह सिर्फ समय की बात है। चुनाव आयोग में वरिष्ठ लोग अब कह रहे हैं कि हम यह और नहीं कर सकते।'



भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटेगी, अमेरिका में दोगुनी हो जाएगी

इस्लाम 2035 तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर धार्मिक आबादी में हो रहे बदलावों को लेकर अमेरिका की प्यू रिसर्च सेंटर की नई रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक, दुनिया की आबादी 2050 तक 9.30 अरब पहुंच सकती है, जो 2010 में करीब 6.90 अरब थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 2010 के मुकाबले 2050 तक मुस्लिम आबादी करीब 73% बढ़ सकती है। यानी मुसलमानों की आबादी 1.6 अरब से बढ़कर लगभग 2.76 अरब हो जाएगी। 2020 से 2050 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 17.6 करोड़ बढ़ने का अनुमान है। हालांकि, देश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटने का अनुमान है। इसके बावजूद 2070 तक हिंदू भारत की कुल आबादी के तीन-चौथाई से ज्यादा बने रहेंगे। इस दौरान अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी हो जाएगी।



अमेरिका में 90 लाख हो जाएगी हिंदू आबादी

अमेरिका में भी हिंदुओं की आबादी दोगुने से ज्यादा होने का अनुमान है। 2020 में यहां करीब 40 लाख हिंदू थे, जिनकी संख्या 2070 तक बढ़कर 90 लाख हो सकती है। इस क्षेत्र की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से बढ़कर 2 प्रतिशत होने का अनुमान है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन ऐसे क्षेत्र होंगे, जहां हिंदुओं की कुल संख्या में गिरावट आने की संभावना है।

मुस्लिम महिलाओं के औसतन बच्चों की संख्या ज्यादा

प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक, पिछले कुछ दशक में भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है। हालांकि, मुस्लिम महिलाओं के औसतन बच्चों की संख्या हिंदू महिलाओं से अधिक है। इसके अलावा भारत में मुस्लिम आबादी का आयु वर्ग भी अपेक्षाकृत युवा है। इन दोनों कारणों से आने वाले दशकों में देश की आबादी में मुस्लिमों का अनुपात बढ़ने और हिंदुओं की हिस्सेदारी में मामूली कमी आने का अनुमान है। प्यू रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2035 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। फिलहाल दुनिया में 2.27 अरब ईसाई और 2.02 अरब मुस्लिम हैं। अनुमान है कि 2035 तक मुस्लिम आबादी बढ़कर 2.57 अरब और ईसाई आबादी 2.52 अरब हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर सबसे ज्यादा है। 2020 से 2025 के बीच मुस्लिम महिलाओं में प्रति महिला औसतन 3.1 बच्चे पैदा हुए, जबकि ईसाई महिलाओं में यह आंकड़ा 2.5 और अन्य धर्मों में 1.6 रहा। प्यू के अनुमान के मुताबिक, 2070 तक दुनिया में मुस्लिमों की आबादी 3.6 अरब से ज्यादा हो सकती है।

दाऊद के पुश्तैनी घर 'मुसाफिरखाना' पर बुलडोजर एक्शन रोका गया

बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, बीएमसी ने गुरुवार को कार्रवाई शुरू की थी

इमारत मस्जिद का हिस्सा भी था शामिल



मुंबई। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के के पुश्तैनी घर 'मुसाफिरखाना' को गिराने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने 23 नवंबर तक इमारत की मौजूदा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह इमारत दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार इलाके की पाकमोडिया स्ट्रीट पर स्थित है। बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने गुरुवार को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की थी। इमारत को गिराने की कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण से भी जुड़ी है। यह मकान मस्जिद का हिस्सा है। बीएमसी ने कहा था कि इमारत का केवल जर्जर हिस्सा गिराया जाएगा। मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा।

1939 में बनी थी इमारत, सी-1 श्रेणी में रखा गया

हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना नाम की यह इमारत 1939 में बनी थी। बीएमसी ने इसे जर्जर और खतरनाक घोषित करते हुए सी-1 श्रेणी में रखा था। इस श्रेणी में ऐसी इमारतें आती हैं जिन्हें खतरनाक मानकर गिराना जरूरी होता है। बीएमसी ने 18 और 19 नवंबर को इमारत गिराने की योजना बनाई थी। कार्रवाई के लिए मौके पर बड़ी संख्या में निगम कर्मचारी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पूरी इमारत को चारों तरफ से नीली टिन की चादरों से ढक दिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, भारी पुलिस सुरक्षा के बीच तोड़फोड़ की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई थी।

तूफान अकवान से पहले ओडिशा से 80 हजार लोग शिफ्ट

6 जिलों में 3 दिन स्कूल-आंगनवाड़ी बंद, 10 राज्यों में असर की आशंका, 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

विशाखापट्टनम/चेन्नई/भुवनेश्वर। *चक्रवाती तूफान अकवान के खतरे को देखते हुए ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ओडिशा में करीब 80 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं, छह जिलों में 21 नवंबर तक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। तूफान का असर देश के 10 राज्यों में देखने को मिल सकता है। इससे निपटने के लिए 74 रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया है।*

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, चक्रवात के आज आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के पुरी के बीच तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरें उठने का खतरा है। इससे पहले गुरुवार को न्यूज एजेंसी एएनआई ने तूफान के तट से टकराने का अनुमान जताया था। चक्रवात के प्रभाव से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियां अलर्ट पर हैं। रेलवे ने भी एहतियातन तीन ट्रेनों के रवाना होने के समय में बदलाव किया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।



10 राज्यों में दिखेगा तूफान का असर

1. **आंध्र प्रदेश :** चक्रवात का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश में होने की आशंका है। आज तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।
2. **ओडिशा :** आज और कल राज्य में भारी बारिश का अनुमान है। गंजाम, गजपति, रायगढ़ा, कोरापुट और मलकानगिरी में ज्यादा असर हो सकता है। निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा है।
3. **तमिलनाडु :** उत्तरी तमिलनाडु में भी भारी बारिश हो सकती है। चेन्नई सहित तटीय इलाकों में जलभराव की आशंका है।
4. **पुडुचेरी :** पुडुचेरी और कराईकल में आज भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका गया है।
5. **तेलंगाना :** राज्य के पूर्वी हिस्सों में आज और 21 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय बाढ़ का खतरा है।
6. **पश्चिम बंगाल :** दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर और झारग्राम में आज भारी बारिश हो सकती है।
7. **झारखंड :** आज और कल कुछ इलाकों में बारिश और कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है।
8. **छत्तीसगढ़ :** यहां तूफान सीधे नहीं टकराएगा, लेकिन आज और कल दक्षिणी और उत्तरी जिलों में बारिश हो सकती है।
9. **बिहार :** गया, नवादा समेत पांच जिलों में आज और 21 नवंबर को बारिश की संभावना है।
10. **मध्य प्रदेश :** राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले दो दिनों तक बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

जब बच्चे बोलते हैं, व्यवस्था को सुनना पड़ता है

(लेखक- सुनील कुमार गुप्ता)

-बचपन के सपने और उनकी पुकार, सुने सरकार

(20 नवंबर, विश्व बाल अधिकार दिवस पर विशेष)

भोपाल। 20 नवंबर को दुनिया बाल अधिकार दिवस मनाती है। सन् 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसी दिन बाल अधिकारों की घोषणा और सन् 1989 में बाल अधिकार अभिसमय (सम्मेलन) स्वीकार किया। भारत ने बच्चों के जीवन, विकास, सुरक्षा, शिक्षा, समानता और सहभागिता के अधिकारों को मान्यता दी है। कानून और योजनाएं हैं, फिर भी क्या हर बच्चा अपना बचपन जी पा रहा है?

जब एक लड़की अपना बाल विवाह रुकवाती है, जब किशोरियां माहवारी पर चुप्पी तोड़ती हैं और जब बच्चे स्कूल की दूरी, बस किराये, शिक्षकों की कमी या पीने के पानी जैसी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरते हैं, तब वे केवल शिकायत नहीं कर रहे होते, वे अपने अधिकारों का अर्थ समझा रहे होते हैं। ऐसे क्षणों में समाज और व्यवस्था, दोनों से सवाल पूछे जाने चाहिए कि बच्चों की आवाज आखिर कितनी सुनी जाती है और उनके लिए क्या किया जाता है?

मध्यप्रदेश में बच्चों की अपनी पहलें बताती हैं कि वे केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि बदलाव के भागीदार भी हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें जानकारी, सुरक्षित मंच और बोलने का अवसर मिले।

पूनम ने अपना विवाह रुकवाया, अब अपने पैरों पर खड़ी है

भोपाल की मदर इंडिया कॉलोनी में रहने वाली पूनम (बदला हुआ नाम) की शादी परिवार ने कम उम्र में तय कर दी थी। घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन पूनम के मन में अपने भविष्य को लेकर अलग आकांक्षाएं थीं। वह लैंगिक समानता के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था सरोकार के साथ बाल विवाह के विरुद्ध नुक्कड़ नाटकों में हिस्सा लेती थी। इन नाटकों में वह स्वयं लोगों को बताती थी कि कम उम्र में विवाह लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सपनों और भविष्य को कैसे प्रभावित करता है। जब वही परिस्थिति उसके जीवन में आई, उसने परिवार से बात की, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को फोन किया और विवाह रुकवा लिया। सरोकार की संस्थापक-सचिव कुमुद सिंह ने यह प्रसंग साझा करते हुए बताया है कि पूनम ने आगे पढ़ाई की, एमबीए पूरा किया और अब अपनी ट्रेडिंग कंपनी चला रही है।

यह सरकारी योजना का आंकड़ा नहीं, जागरूकता और आत्मविश्वास की कहानी है। लेकिन कितनी पूनम अपनी शादी रोक पाती हैं? कितनी लड़कियां सामाजिक दबाव में पढ़ाई छोड़ देती हैं? बाल विवाह रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई के साथ परिवारों, समुदायों, विद्यालयों और पंचायतों से लगातार संवाद जरूरी है। लड़कियों को ऐसा वातावरण भी चाहिए जिसमें वे अपने जीवन के फैसले ले सकें।

ह्स्न।स–6 (2023-24) के अनुसार मध्यप्रदेश में 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 20 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ था। ह्स्न।स–5 में यह अनुपात 23.1 प्रतिशत था। गिरावट उम्मीद जगाती है, लेकिन हर पांचवीं लड़की बाल विवाह का शिकार हुई है। चुनौती अब भी बड़ी है। कुमुद सिंह के अनुसार, कई बाल विवाह दर्ज ही नहीं हो पाते। इसलिए कानून के साथ संवाद और लड़कियों की शिक्षा में निवेश जरूरी है।

माहवारी पर चुप्पी टूटे, तभी गरिमा और स्वास्थ्य का अधिकार पूरा होगा

सरोकार की एक और पहल किशोरी बालिकाओं को मासिक धर्म के बारे में खुलकर बात करने का साहस देने से जुड़ी है। घर में धीमी आवाज में होने वाली बातचीत और विद्यालयों में झिझककर पूछे जाने वाले सवालों को संस्था ने संवाद का विषय बनाया। स्कूलों और बस्तियों में किशोरियों को शरीर में होने वाले बदलाव समझने, प्रश्न पूछने और बिना संकोच बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लड़कों और समुदाय को भी जोड़ा गया, क्योंकि यह चुप्पी पूरे समाज की सोच से जुड़ी है।

माहवारी स्वाभाविक है, लेकिन मिथक और सुविधाओं की कमी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान प्रभावित करते हैं। क्या हर विद्यालय में किशोरियां भरोसे से सवाल पूछ सकती हैं? क्या घरों में पुरुष सदस्य भी इसे सामान्य प्रक्रिया मानते हैं? मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार उत्पाद उपलब्ध कराने भर से पूरा नहीं होता; जानकारी, स्वच्छ शौचालय, पानी, सम्मान और भेदभाव से मुक्ति भी जरूरी है।

दोनों पहलें बताती हैं कि लड़कियों को संरक्षण के साथ जानकारी, आत्मविश्वास और निर्णय की स्वतंत्रता भी चाहिए।

आंकड़े बताते हैं बचपन की चुनौतियां

पोषण भी गंभीर सवाल उठाता है। ह्स्न।स–5 (2019-21) के अनुसार मध्यप्रदेश में पांच वर्ष से कम आयु के 35.7 प्रतिशत बच्चे अवरुद्ध विकास और 33 प्रतिशत बच्चे कम वजन की समस्या से प्रभावित थे। ह्स्न।स–6 (2023-24) की उपलब्ध राज्य तथ्य-पत्रिका में इन पोषण संकेतकों के तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; इसलिए पुराने आंकड़ों को वर्तमान स्थिति बताकर पेश करना उचित नहीं होगा।

शिवपुरी के सहरिया बहुल गांवों में कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए विकास संवाद समिति और बाल अधिकारों पर काम करने वाली संस्था क्राय के सहयोग से समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन के प्रयास किए गए। कई वर्षों तक चली इस पहल ने पोषण को केवल परिवार की जिम्मेदारी मानने के बजाय आंगनवाड़ी, समुदाय और सार्वजनिक व्यवस्था की साझा जिम्मेदारी बनाने पर जोर दिया। बच्चे का पोषण भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मातृ स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ा है। किसी एक योजना से समस्या हल नहीं होगी; सेवाओं का समन्वय जरूरी है।



शिक्षा के क्षेत्र में भी नामांकन और पढ़ाई पूरी करने के बीच दूरी बनी हुई है। ष्ठड्ढुस्थ+ 2024-25 के अनुसार मध्यप्रदेश में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 16.8 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 11.5 प्रतिशत था। पढ़ाई छूटने के पीछे आर्थिक दबाव, दूरी, परिवहन, घरेलू जिम्मेदारियां और विद्यालयी सुविधाओं की कमी हो सकती है। इसे केवल पारिवारिक निर्णय मानना समस्या की जड़ से नजर हटाना है।

जब बच्चे खुद सवाल करते हैं, व्यवस्था को जवाब देना पड़ता है

मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचलों से बच्चों की सामूहिक पहल की कहानियां सामने आई हैं। अलीराजपुर के चिकड़ा गांव में बच्चों ने विद्यालय में शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति का मुद्दा उठाया। 12 वर्षीय दामा रामिया ने अपनी परेशानी परिवार और सरपंच के सामने रखी। इसके बाद बच्चों ने बाल पंचायत बनाई। धीरे-धीरे 30 गांवों के लगभग 100 बच्चे इससे जुड़े और उन्होंने अपनी शिकायत प्रशासन तक पहुंचाई। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इस पहल के बाद क्षेत्र के 21 विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठे।

अगस्त 2026 में विदिशा जिले के सिरोंज में छात्राओं ने बस किराये में बढ़ोतरी का विरोध किया। ग्रामीण इलाकों से स्कूल आने वाली लड़कियों का कहना था कि किराया बढ़ने से पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो सकता है। उनके प्रदर्शन के बाद प्रशासन और बस संचालकों के बीच बातचीत हुई और छात्राओं के लिए पुरानी रियायती दर बहाल की गई। यह स्कूल तक पहुंच और शिक्षा जारी रखने के अधिकार का सवाल था।

उज्जैन में रानी लक्ष्मीबाई शासकीय सराफा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शहर से लगभग सात किलोमीटर दूर दाऊदखेड़ी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ छात्र-छात्राएं सामने आए। उन्हें चिंता थी कि दूरी बढ़ने से आने-जाने, सुरक्षा और पढ़ाई पर असर पड़ेगा। विद्यार्थियों के विरोध के बाद प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक विद्यालय को मौजूदा परिसर में जारी रखने का आश्वासन दिया। भोपाल में भी लगभग 300 से 400 विद्यार्थियों ने रीजनल स्कूल के प्रस्तावित विलय के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी शैक्षणिक पहचान और विद्यालय की प्रकृति को लेकर चिंता जताई। मांगें असाधारण नहीं थीं- सुरक्षित रास्ता, सस्ता परिवहन, शिक्षक, साफ पानी और बेहतर भवन। क्या इन्हें सुनिश्चित करना व्यवस्था की पहली जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए?

महाकोशल क्षेत्र की इंदिरा ने अपने विद्यालय में पेयजल की समस्या बाल पंचायत में उठाई। बच्चों ने अभिभावकों और स्थानीय प्रशासन तक बात पहुंचाई और विद्यालय में हैंडपंप लगाने की स्वीकृति मिली। शिवपुरी के एक सहरिया गांव में सावित्री (बदला हुआ नाम) ने निजता और सुरक्षा की समस्या से परेशान होकर पत्थरों और बांस से अस्थायी शौचालय बनाया। उसकी पहल से आसपास के गांवों में भी प्रेरणा मिली और 250 से अधिक शौचालयों के निर्माण का रास्ता बना। ये उदाहरण बताते हैं कि बच्चों को निर्णयों में जगह देने से स्थानीय बदलाव संभव है।

संपादकीय

भारत और आसियान

भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का सदस्य न होते हुए भी जिस तरह उसके सम्मेलनों में भागीदारी करता है और इस संगठन के देश इसे महत्ता प्रदान करते हैं, उससे भारत के बढ़ते कद का ही पता चलता है। चूंकि आसियान दक्षिण पूर्व के 11 एशियाई देशों का समूह है और भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, इसलिए वह उसका सदस्य तो नहीं बन सकता, लेकिन इस संगठन के साथ अपने आर्थिक-व्यापारिक सहयोग को बढ़ाकर व्यापक लाभ अवश्य उठा सकता है और वह उसे उठाना ही चाहिए। आसियान के संवाद भागीदार और रणनीतिक साझीदार के रूप में भारत को इस संगठन के साथ अपने संबंध और अधिक प्रगाढ़ करने को इसलिए प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि सभी सदस्य देश भारत के लिए एक बड़ा बाजार बन सकें। यह सही है कि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाने के लिए एक्ट ईस्ट पालिसी बना रखी है और इसके चलते इन देशों के साथ उसका व्यापार भी बढ़ा है, लेकिन इसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि भारत इन देशों को निर्यात कम करता है और आयात अधिक। चूंकि आसियान देश चीन के आर्थिक-व्यापारिक दबदबे के साथ उसकी अतिक्रमणकारी नीतियों से भी त्रस्त हैं, इसलिए भारत को इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल देना चाहिए। भारत को उन कारणों का निवारण भी करना होगा, जिनके चलते उसने खुद को आसियान के नेतृत्व वाले मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा था। इसका एक बड़ा कारण यह आशंका थी कि इस समझौते में शामिल होने से भारत में चीनी सामग्री का आयात बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा तो अब भी हो रहा है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्पष्ट है कि भारत को आसियान देशों के साथ मिलकर चीन के आर्थिक दबदबे का मुकाबला करने के लिए कमर कसनी ही होगी। इसमें भारतीय उद्यमियों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। भारत सरकार के नीति-नियंता और भारतीय उद्यमी इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि आसियान देश कई क्षेत्रों में कहीं आगे निकल गए हैं। इसके चलते इन देशों के औसत लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है। चूंकि ये देश एक सशक्त आर्थिक समूह बन गए हैं, इसलिए विश्व के प्रमुख देश आसियान के मंच को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। आज जब भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है और वह अपनी संतुलनकारी नीति के चलते तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल है, तब उसे आसियान जैसे उन समूहों को कहीं अधिक महत्व देना होगा, जो उसके लिए अधिक फलदायी हो सकते हैं। आसियान के बीच भारत इसलिए आसानी से अपना प्रभाव छोड़ सकता है, क्योंकि इस संगठन के सभी देशों में भारतीय संस्कृति का अच्छा-खासा प्रभाव है। इस सांस्कृतिक जुड़ाव का भी लाभ उठाया जाना चाहिए।

आज जब भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है और वह अपनी संतुलनकारी नीति के चलते तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल है, तब उसे आसियान जैसे उन समूहों को कहीं अधिक महत्व देना होगा, जो उसके लिए अधिक फलदायी हो सकते हैं।

हिंसा, शोषण और अभाव से मुक्त हो भारत का बचपन

(लेखक- ललित गर्ग)

(विश्व बाल दिवस- 20 नवम्बर 2026)

हम में से प्रत्येक को बच्चों के अधिकारों की वकालत करने, उन्हें बढ़ावा देने, उनके शोषण को रोकने, उनका समग्र विकास करने और बच्चों का उत्सव मनाने के लिए एक प्रेरणादायी अवसर के रूप में विश्व बाल दिवस है, यह उस समाज की आत्मपरीक्षा का अवसर है, जो अपने भविष्य को बच्चों की आंखों में देखता है। 20 नवंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस हमें याद दिलाता है कि बच्चे केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। वर्ष 2026 की थीम 'मेरा दिन, मेरे अधिकार, मेरा भविष्य' है। इसी बुनियादी प्रश्न को सामने रखती है कि क्या हमारे बच्चों को वास्तव में अपने अधिकारों के साथ जीने, सपने देखने और अपना भविष्य गढ़ने का अवसर मिल रहा है? भारत में बचपन की तस्वीर विरोधाभासों से भरी है। एक ओर महानगरों के वातानुकूलित कमरों में पलते बच्चे आधुनिक शिक्षा, तकनीक और सुविधाओं से घिरे हैं, तो दूसरी ओर फुटपाथ, झुग्गियों, कारखानों, ढाबों और खेतों में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके हाथों में किताब की जगह औजार हैं। किसी बच्चे के लिए बचपन खेल, शिक्षा और परिवार का स्नेह है, तो किसी के लिए भूख, श्रम, हिंसा और असुरक्षा से जूझने का नाम। यह असमानता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना की भी परीक्षा है।

सबसे गंभीर चुनौती बाल हिंसा और मानसिक दबाव की है। हिंसा का अर्थ केवल बच्चे को पीटना नहीं है। लगातार डांटना, अपमानित करना, डराना, उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करना, उसकी इच्छा और प्रतिभा को नकारना तथा हर समय परिणाम का दबाव बनाना भी हिंसा के ही रूप हैं। आज अनेक अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या किसी प्रतिष्ठित पेशे में जाए। महत्वाकांक्षा गलत नहीं, लेकिन जब माता-पिता की अधूरी इच्छाओं का बोझ बच्चे के कंधों पर रख दिया जाता है, तब शिक्षा विकास का माध्यम न रहकर तनाव का कारण बन जाती है। स्कूल भी इससे अछूते नहीं हैं। अनुशासन के नाम पर अपमान, डर और कठोरता बच्चे के व्यक्तित्व को भीतर से तोड़ सकती है। जिस विद्यालय में बच्चे को प्रश्न पूछने, गलती करने और फिर सीखने का अवसर मिलना चाहिए, वहां भय का वातावरण उसकी रचनात्मकता को कुंठित कर देता है। हमें यह समझना होगा कि डर से आज्ञाकारी बच्चा तो बनाया जा सकता है, लेकिन आत्मविश्वासी नागरिक नहीं।

भारत में बाल मजदूरी, बाल तस्करी, यौन शोषण और भिक्षावृत्ति जैसी समस्याएं आज भी हमारी सामूहिक चेतना एवं राजनीतिक नेतृत्व पर प्रश्नचिह्न हैं। आर्थिक मजबूरी के कारण अनेक बच्चे शिक्षा से दूर होकर श्रम की दुनिया में पहुंच जाते हैं। कुछ खतरनाक उद्योगों और असुरक्षित कार्यस्थलों पर काम करने के लिए विवश होते हैं। कई बच्चे तस्करी के जाल में फंसकर अपने परिवार और बचपन दोनों से दूर हो जाते हैं। सबसे पीड़ादायक स्थिति उन बच्चों की है जिन्हें अपराध, भीख या यौन शोषण के अंधेरे में धकेल दिया जाता है। इन परिस्थितियों में उनसे केवल उनका वर्तमान नहीं छीना जाता, बल्कि भविष्य की संभावनाएं भी छीन ली जाती हैं। गरीबी बचपन की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन गरीबी से भी बड़ी समस्या है अवसरों की असमानता। यदि किसी गरीब परिवार का बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण से वंचित रहता है तो वह अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कैसे करेगा? विकसित भारत का सपना तभी वास्तविक होगा जब विकास की रोशनी गांव, झुग्गी, श्रमिक परिवार और वंचित समुदाय के बच्चे तक पहुंचेगी। किसी राष्ट्र की प्रगति का सही पैमाना उसके सबसे कमजोर बच्चे की स्थिति है।

इसलिए बाल अधिकारों को केवल कानून की पुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय घर, स्कूल और समाज की संस्कृति का हिस्सा बनाना होगा। बच्चे को यह विश्वास होना चाहिए कि वह अपनी समस्या बिना भय के माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति से कह सकता है। परिवार में संवाद की परंपरा विकसित करनी होगी। माता-पिता को बच्चों के साथ केवल उनकी पढ़ाई और परीक्षा की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके डर, मित्रता, सपनों, असफलताओं और भावनाओं को भी सुनना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में भी बड़ा परिवर्तन आवश्यक है। शिक्षा का लक्ष्य केवल अंक और रोजगार नहीं, बल्कि संवेदनशील, आत्मनिर्भर, नैतिक और मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य बनाना होना चाहिए। बच्चों को अधिकारों के साथ कर्तव्यों, संविधान, लैंगिक सम्मान, डिजिटल सुरक्षा, आत्मरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया जाना चाहिए। सरकार को बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ बाल श्रम, तस्करी और यौन अपराधों के विरुद्ध तंत्र को और मजबूत करना होगा। गरीब बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य को आर्थिक सहायता से जोड़ना भी जरूरी है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि बच्चों की सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पड़ोस में किसी बच्चे से दुर्व्यवहार हो रहा हो, किसी दुकान या कारखाने में बाल मजदूर दिखाई दे, कोई बच्चा लगातार भय में जी रहा हो या उसके साथ शोषण की आशंका हो, तो ष्हमें क्या लेना-देना है ष कहकर आगे बढ़ जाना सामाजिक अपराध के प्रति मौन स्वीकृति है। बच्चे की रक्षा के लिए समाज को संवेदनशील प्रहरी बनना होगा।

विश्व बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के सामने उभरती नई चुनौतियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भी एक गंभीर विषय बनकर सामने आई है। एआई शिक्षा, रचनात्मकता और ज्ञान-विस्तार का प्रभावी साधन हो सकता है, लेकिन उसका अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग बच्चों की सोचने-समझने की मौलिक क्षमता, कल्पनाशक्ति, एकाग्रता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। चैटबॉट पर अत्यधिक निर्भरता बच्चों को स्वयं प्रश्न पूछने, उत्तर खोजने और गलतियों से सीखने की प्रक्रिया से दूर कर सकती है।

साथ ही, एआई से बने भ्रामक या अनुपयुक्त कंटेंट, डीपफेक, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, निजता के खतरे और बच्चों के मानसिक संसार पर बढ़ते डिजिटल दबाव जैसी चुनौतियां भी चिंता का विषय हैं। इसलिए आज आवश्यकता केवल बच्चों को एआई से परिचित कराने की नहीं, बल्कि उन्हें एआई के सुरक्षित, संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की शिक्षा देने की है, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता बच्चों की बुद्धि का विकल्प नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा और रचनात्मकता को विकसित करने का सहायक माध्यम बने।



मूल्य भावना का

भगवान बुद्ध जेतवन में ठहरे हुए थे। हर सुबह वह भिक्षावृत्ति को निकलते तो उन्हें मार्ग में एक किसान अपने खेत में काम करता मिलता। अपने कार्य के प्रति उसकी निष्ठा देख बुद्ध के मन में उसके लिए करुणा उमड़ी। वह प्रतिदिन वहां रुककर उस किसान को कुछ उपदेश देने लगे। जब उस किसान की फसल तैयार हुई तो उसने संकल्प किया कि वह अपनी फसल का एक हिस्सा भगवान बुद्ध को और भिक्षु संघ को भेंट करेगा। दुर्योगवश उसी रात मूसलाधार वर्षा हुई और उसकी सारी फसल चौपट हो गई। अगले दिन जब भगवान बुद्ध वहां से गुजरे तो उन्होंने किसान को वहां रोता हुआ पाया। पूछने पर किसान उनको सारी घटना सुना कर बोला, ''प्रभु! मुझे दुख अपने नुक्सान का नहीं, वरन इस बात का है कि मैं आपकी सेवा का यह अवसर चूक गया''

बुद्ध मुस्कराए और बोले, 'भंते! मूल्य वस्तुओं का नहीं, भावनाओं का होता है। तुम्हारे हृदय में उमड़ी भावनाएं तो मुझ तक कल ही पहुंच गई थीं। इनके कारण तुम उससे ज्यादा पुण्य के भागी बन गए हो, जितना तुम उस फसल को समर्पित करके बनते। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है'' किसान की आंखें यह सुनकर नम हो उठीं।



विचार मंथन

विकास की अंधी दौड़ में दम तोड़ता पर्यावरण, आखिर जवाबदेह कौन?

(लेखक- सनत जैन)

प्रदूषण की बढ़ती समस्या केवल मौसम, पराली, पटाखों और वाहनों का परिणाम नहीं, बल्कि विकास की नीतियों, प्रशासनिक लापरवाही और पर्यावरण संरक्षण के प्रति कमजोर इच्छाशक्ति पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। भारत आज विकास की जिस दौड़ में शामिल है, उसमें आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विस्तार, सड़कों का निर्माण, बड़े-बड़े भवन और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की होड़ लगी हुई है। निश्चित रूप से विकास किसी भी देश की आवश्यकता है, सवाल यह है, क्या विकास की कीमत प्रकृति को नष्ट करके चुकाई जानी चाहिए? क्या जंगलों को काटकर, पहाड़ों को खोखला करके, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करके और हवा-पानी को प्रदूषित करके ही विकास किया जा सकता है? आर्थिक प्रगति ही वास्तव में देश का विकास कहलाएगी? आज भारत के सामने यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। पिछले डेढ़ दशक में देश के अनेक हिस्सों में जिस तेजी से निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है। उसने पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर चुनौती दी है। हिमालयी क्षेत्र, उत्तराखंड, बस्तर के घने जंगल, तटीय इलाके और देश के प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र विकास परियोजनाओं के दबाव में पर्यावरण की दृष्टि से दम तोड़ रहे हैं। जिन स्थानों पर निर्माणकार्यों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत थी वहां भी पर्यावरणीय प्रभावों का पर्याप्त आकलन किए बिना परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की शिकायतें सामने आती हैं। इसके परिणामस्वरूप भूस्खलन, बाढ़, जंगलों का विनाश और जैव विविधता पर संकट जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था भी अब विकास के नाम पर पर्यावरण के मामलों में अनदेखी कर रही है। इसने चिंता को और बढ़ा दिया है।

सबसे चिंताजनक स्थिति वायु प्रदूषण की है। दिल्ली-एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के अनेक शहरों में हवा की गुणवत्ता लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। सर्दियों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी तक पहुंच जाता है। लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, बच्चों और बुजुर्गों पर इसका विशेष दुष्प्रभाव पड़ रहा है। श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। प्रदूषण का प्रभाव केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहर और कस्बे भी इसकी चपेट में आ गये हैं। इस समस्या के लिए केवल पराली, पटाखों, वाहनों या मौसम को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, ताप विद्युत संयंत्रों का उत्सर्जन, निर्माण स्थलों की धूल, कचरा जलाना और शहरी नियोजन की कमजोरियां भी प्रदूषण के बड़े कारण हैं। इन सभी पर नियंत्रण की जिम्मेदारी पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों की है। इसके बावजूद जब प्रदूषण बढ़ता है, तो जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनों और संस्थाओं की कमी नहीं है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण और न्यायपालिका भी पर्यावरणीय मामलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके बावजूद असली चुनौती इन कानूनों और आदेशों को जमीन पर लागू करने की है। यदि किसी परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देते समय उसके दीर्घकालिक प्रभावों का निष्पक्ष आकलन नहीं होगा, यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, यदि पौधारोपण के नाम पर केवल कागजी उपलब्धियां दिखाई जाएंगी, तो पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य भारत में कभी पूरा नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार की जो गंगा भारत में बह रही है, जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में मामला और भी जटिल होता चला जा रहा है।

चीन और यूरोप के कई देशों के अनुभव बताते हैं, औद्योगिक विकास के साथ प्रदूषण नियंत्रण की तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरणीय निगरानी में लगातार निवेश करना जरूरी है। भारत को इन अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है। केवल योजनाएं बनाने और हजारों करोड़ रुपये खर्च करने से परिणाम नहीं मिलेंगे। यह देखना होगा कि कितने पेड़ वास्तव में लगाए गए, कितने जीवित बचे, उद्योगों ने उत्सर्जन कितना घटाया और शहरों की हवा कितनी स्वच्छ हुई। यदि उसमें खराबी आई है तो जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है, पर्यावरण संरक्षण को सरकारी औपचारिकता के बजाय राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाए। विकास परियोजनाओं की मंजूरी में पारदर्शिता हो, पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, वन भूमि और जलस्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की जवाबदेही तय हो। साथ ही नागरिकों को भी सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा बचत, कचरा प्रबंधन और वृक्षारोपण में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण को विकास विरोधी नहीं, बल्कि विकास की अनिवार्य शर्त माना जाए।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एंथ्रोपिक ने आईपीओ से रचा इतिहास, निवेशकों का एआई पर गहरा भरोसा

नई दिल्ली ।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनी एंथ्रोपिक ने दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ पेश कर शेयर बाजार में इतिहास रचा है। निवेशकों की जबरदस्त मांग के चलते कंपनी के शेयर शुरुआती अनुमानित मूल्य 70-78 डॉलर से कहीं अधिक, 83 डॉलर प्रति शेयर पर अलॉट किए गए हैं। यह एआई तकनीक में बढ़ते वैश्विक भरोसे का स्पष्ट संकेत है, हालांकि कंपनी के सामने अब भी कई बड़ी चुनौतियां हैं।

नैस्डैक पर एएनटी टिकर के तहत कारोबार शुरू करने जा रहे एंथ्रोपिक के एआई मॉडल क्लॉड, विशेषकर क्लॉड कोड की सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बीच लोकप्रियता ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है। कंपनी की फाइलिंग के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 तक उसका सालाना राजस्व रन रेट 81 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, और 1 लाख डॉलर से अधिक राजस्व वाले ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। हालांकि, इस अभूतपूर्व वृद्धि के साथ बड़ी लागतें भी जुड़ी हैं। एआई मॉडल बनाने और चलाने के लिए आवश्यक विशाल कंप्यूटिंग क्षमता व डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। 2026 की पहली छमाही में लगभग 9 अरब डॉलर और तीसरी तिमाही में 5 अरब डॉलर के खर्च के कारण कंपनी को तीसरी तिमाही में 567 मिलियन डॉलर का ऑपरेटिंग लॉस हुआ। अमेज़ॉन व गूगल के साथ 900 अरब डॉलर के कंप्यूटिंग खर्च की प्रतिबद्धता भविष्य में भी बड़े निवेश की आवश्यकता दर्शाती है। साथ ही, एंथ्रोपिक को एआई सुरक्षा व तकनीक के तेजी से विकास से जुड़े सवालों से भी निपटना है। अब निवेशकों की नजर नैस्डैक पर एंथ्रोपिक के शेयरों की लिस्टिंग और उनके शुरुआती प्रदर्शन पर टिकी है।

कार्नेलियन का फ्लेक्सी कैप फंड जल्द,निवेशकों को मिलेगा निवेश का मौका

सेबी के पास ड्राफ्ट जमा, 500 रुपए से शुरू कर सकेंगे निवेश

नई दिल्ली ।

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए खुशखबरी! कार्नेलियन म्यूचुअल फंड एक नई फ्लेक्सी कैप स्कीम कार्नेलियन फ्लेक्सी कैप फंड लाने की तैयारी में है।

इसके लिए ड्राफ्ट दस्तावेज बाजार नियामक सेबी को सौंप दिए गए हैं। यह फंड निवेशकों को विभिन्न बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों- लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश का व्यापक अवसर प्रदान करेगा। यह एक ओपन-एंडेड स्कीम होगी, जिसका अर्थ है कि निवेशक अपनी सुविधा अनुसार इसमें कभी भी पैसा लगा या निकाल सकते हैं। फंड मैनेजर के पास बाजार की परिस्थितियों के अनुसार लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों के बीच निवेश आवंटित करने का पूरा लचीलापन होगा। निवेशक इस स्कीम में न्यूनतम 500 रुपये से शुरुआत कर सकेंगे, जिसके बाद एक रुपये के गुणक में अतिरिक्त निवेश संभव होगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) की न्यूनतम राशि भी 500 रुपये रखी गई है, जिसमें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और तिमाही जैसे कई विकल्प उपलब्ध होंगे। दैनिक एसआईपी के लिए कम से कम 30 किस्तों और अन्य विकल्पों के लिए 12 किस्तों की आवश्यकता होगी।

चंदा कोछड़ को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने मुकदमे की मंजूरी रद्द की

निदेशक मंडल को नहीं था अधिकार, आरबीआई के पास है मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का हक

नई दिल्ली ।

बंबई उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक चंदा कोछड़ को वीडियोकॉन ऋण मामले में बड़ी राहत प्रदान की है।

न्यायालय ने उन पर मुकदमा चलाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया है, यह कहते हुए कि यह अधिकार निदेशक मंडल के पास नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास था। अदालत ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत किसी बैंक के प्रबंध निदेशक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अधिकार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास है, न कि बैंक के निदेशक मंडल के पास। न्यायालय ने यह भी पाया कि 15 मई, 2023 के मंजूरी आदेश में तथ्यों पर उचित विचार नहीं किया गया था और सबूतों की स्वतंत्र जांच नहीं हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने मंजूरी और मामले में विशेष सीबीआई अदालत की ओर से की गई आगे की सभी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया। सीबीआई की ओर से इस फैसले पर 8 सप्ताह की रोक लगाने की मांग को भी अदालत ने खारिज कर दिया। चंदा कोछड़ ने पीसी एक्ट की धारा 19 के तहत दी गई इस मंजूरी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

शेयर बाजार भारी तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 989, निफ्टी 286 अंक उछला

मुम्बई।

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को भारी तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आया है। आज वाहन और बैंक शेयरों में में हुई खरीदारी से भी बाजार को बल मिल मिला। विदेशी फंड्स की लगातार आवक और कमोडिटी की कीमतों में नरमी से भी बाजार ऊपर आया। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 989.94 अंक उछलकर 83,021.75 पर बंद हुआ। वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 286.35 अंक बढ़कर 25,514.30 पर बंद हुआ था।

आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स पैक में सबसे ज्यादा मारुति सुजुकी के शेयर 7.58 फीसदी उछले। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा , एक्सिस बैंक , हिंदुस्तान यूनिलीवर , भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर भी उछले। वहीं दूसरी तरफ, आईटी शेयरों में गिरावट रही। , टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) के शेयर सबसे अधिक गिरे। बाजार की इस तेजी के पीछे विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी का भी बड़ा हाथ रहा। विदेशी निवेशकों ने बुधवार को 5,866.78 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे।

वहीं आज एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि चीन का शंघाई एएसएफ कंपोजिट और हॉन्गकॉन्ग



का हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपीय बाजारों में भी ज्यादातर तेजी रही।

अमेरिकी बाजारों की बात करें तो उसमें मिला-जुला रुख रहा। डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 1.11 फीसदी गिरा, एसएंडपी 500 में 0.23 फीसदी की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.42 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ था। वहीं इससे पहले आप सुबह भारतीय शेयर बाजारों में मुनाफावसूली का दबाव देखने को मिल रहा। बेंचमार्क इंडेक्स लगातार दूसरे सेशन में गिर गया है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 81700 के नीचे फिसल गया है। निफ्टी भी कमजोरी के चलते 25100 तक फिसला।

सोने के भाव में गिरावट,चांदी भी फिसली

सोने का भाव 1,28,858, चांदी का भाव लगभग 1,60,325 रुपए

नई दिल्ली ।

अमेरिकी डॉलर में लगातार मजबूती और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की आशंका से सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। खबर लिखे जाने के समय दोनों के भाव गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सोने के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,494 रुपये की गिरावट के साथ 1,28,320 रुपये के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 1,29,814 रुपये था। खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 956 रुपये की गिरावट के साथ 1,28,858 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोने के वायदा भाव ने इस साल 1,59,700 रुपये के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत सुस्त रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 2,401 रुपये की गिरावट के साथ 1,60,325 रुपये पर खुला। पिछला बंद भाव 1,60,734 रुपये था। खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 997 रुपये की गिरावट के साथ 1,59,737 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव ने इस साल 4,20,048 रुपये किलो के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के भाव सुस्ती के साथ कारोबार कर रहे हैं। कॉमेक्स पर सोना 3,730.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 3,741.90 डॉलर प्रति औंस था। खबर लिखे जाने के समय यह 26.80 डॉलर की गिरावट के साथ 3,715.10 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

ईपीएफओ की नई योजना, रिटायरमेंट के बाद पीएफ किस्तों में मिलेगा

- सेवानिवृत्ति के बाद भी खाते में रहेगा पैसा, मिलेगा ब्याज

नई दिल्ली।

रिटायरमेंट के बाद भविष्य निधि (पीएफ) का पैसा एक साथ निकालने के बजाय अब धीरे-धीरे निकालने की सुविधा मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इसके लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) लाने पर विचार कर रहा है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद भी आपके पैसे पर ब्याज मिलता रहेगा और नियमित आय सुनिश्चित होगी। ईपीएफओ रिटायरमेंट फंड से पैसा निकालने के लिए अपने सदस्यों को अधिक विकल्प देने की तैयारी में है। प्रस्तावित एसडब्ल्यूपी योजना के तहत, कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार पीएफ खाते से किस्तों में पैसा निकाल सकेंगे। यह मौजूदा व्यवस्था से अलग होगा, जहां कर्मचारी 55 साल की उम्र में रिटायर होने पर पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं। एसडब्ल्यूपी से यह सुनिश्चित होगा कि रिटायरमेंट के बाद भी आपका फंड निवेशित रहे और उस पर ब्याज मिलता रहे, जिससे आपको नियमित आय का विकल्प मिलेगा। इन अहम प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए ईपीएफओ के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक 19 नवंबर को होने वाली है।

म्यूचुअल फंड निवेशकों का रुझान बदला, लार्जकैप फंडों ने स्मॉलकैप को पछाड़ा

बीते एक महीने में लार्जकैप फंडों ने दिया 9.8 फीसदी का शानदार रिटर्न

नई दिल्ली ।

बीते एक महीने में भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां लार्जकैप फंडों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न देकर स्मॉलकैप और मिडकैप फंडों को काफी पीछे छोड़ दिया है। इस अवधि में लार्जकैप फंडों ने जहां 9.8 फीसदी का प्रभावशाली रिटर्न दिया, वहीं स्मॉलकैप फंडों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और उन्हें केवल 0.7 फीसदी का रिटर्न मिला। मिडकैप फंडों ने 4 फीसदी का रिटर्न दर्ज किया। रिटर्न के साथ-साथ, निवेशकों के रुझान में भी स्पष्ट बदलाव आया है, जिसमें लार्जकैप फंडों में शुद्ध निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि स्मॉलकैप फंडों से निवेश घटा है। अक्टूबर 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते एक महीने में भारतीय शेयर बाजार ने शानदार वापसी की और भारतीय इक्विटी फंड का औसत प्रदर्शन 6 फीसदी रहा। इसके विपरीत, वैश्विक इक्विटी फंड और सोने-चांदी में निवेश करने वाले फंडों में गिरावट देखी गई। रिपोर्ट बताती है कि लार्जकैप म्यूचुअल फंड में शुद्ध निवेश 9,634 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,887 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 44 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। वहीं, स्मॉलकैप फंड में शुद्ध निवेश 8,071 करोड़ रुपये से घटकर 5,152 करोड़ रुपये रह गया, जिसमें लगभग 36 फीसदी की गिरावट आई। जानकारों का मानना है कि इस



तेजी के पीछे विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में वापसी और उनका बड़ी कंपनियों के शेयरों पर केंद्रित ध्यान एक प्रमुख वजह रहा। वैश्विक स्तर पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)से जुड़ी कंपनियों में अत्यधिक निवेश पर सवाल उठने और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण ब्याज दरों में वृद्धि की आशंकाओं ने सोने-चांदी जैसी परिसंपत्तियों पर दबाव डाला।

ऐसे माहौल में निवेशकों ने भारत जैसे उभरते बाजारों का रुख किया, जहाँ उन्हें स्थिर बड़ी कंपनियों में निवेश सुरक्षित लगा।

डीएसपी और यूनियन म्यूचुअल फंड में आईडीसीडब्ल्यू का ऐलान, मिलेगा आय वितरण

नई दिल्ली ।

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। डीएसपी म्यूचुअल फंड और यूनियन म्यूचुअल फंड ने अपनी दो लोकप्रिय स्कीम्स में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉल (आईडीसीडब्ल्यू) के तहत भुगतान करने की घोषणा की है। यह कदम निवेशकों को आय वितरण का एक अवसर प्रदान करेगा। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने अपनी डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड स्कीम के रेगुलर और डायरेक्ट, दोनों प्लान के आईडीसीडब्ल्यू विकल्प में 0.55 रुपये प्रति यूनिट देने का ऐलान किया है। वहीं यूनियन म्यूचुअल फंड ने यूनियन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के आईडीसीडब्ल्यू विकल्प में 0.10 रुपये प्रति यूनिट देने की घोषणा की है। इन दोनों स्कीम्स के लिए रिकॉर्ड डेट 19 नवंबर निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि बाजार नियामक सेबी ने अप्रैल 2021 से लाभांश (डिविडेंड) का नाम बदलकर आईडीसीडब्ल्यू कर दिया था। उदाहरण के तौर पर, डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की 10,000 यूनिट पर 5,500 रुपये और यूनियन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की उतनी ही यूनिट पर 1,000 रुपये का भुगतान होगा।

खुदरा कर्ज में बूम, पर कुछ श्रेणियों में बढ़ रही डिफॉल्ट की चिंता

नई दिल्ली ।

देश में खुदरा कर्ज का बाजार तेजी से फल-फूल रहा है, पर इसकी चमक के पीछे कुछ श्रेणियों में बढ़ते डिफॉल्ट (किस्त चुकाने में देरी) की चिंताएं भी मंडरा रही हैं। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, खासकर गोल्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और पर्सनल लोन में शुरुआती दबाव के संकेत मिल रहे हैं। सितंबर के अंत तक देश का कुल खुदरा कर्ज पोर्टफोलियो सालाना आधार पर 18.8 फीसदी बढ़कर 185.2 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। गोल्ड लोन 60.6 फीसदी की वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली कर्ज श्रेणी बनकर उभरा। इसके बाद सिक्योर्ड बिजनेस लोन (45.2 फीसदी) और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन (44.5 फीसदी) का स्थान रहा। हालांकि, इस वृद्धि के साथ ही कुछ चिंताजनक रुझान भी सामने आए हैं।

गोल्ड लोन में 31 से 90 दिन तक किस्त बकाया रहने के मामले



जून के 0.9 फीसदी से बढ़कर सितंबर में 1.3 फीसदी हो गए हैं। वहीं, 31 से 180 दिन तक की बकाया कर्ज की हिस्सेदारी भी 1.3 फीसदी से बढ़कर 1.6 फीसदी हो गई है।

यह स्थिति बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के बीच कर्ज लेने वालों पर बढ़ते वित्तीय दबाव को उजागर करती है।

यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू करने के प्रस्ताव फिलहाल टला

आगामी चुनावों और व्यापारी विरोध के चलते केंद्र का निर्णय

नई दिल्ली ।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले यूपीआई ग्राहकों और दुकानदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है।

केंद्र सरकार ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) यानी पेमेंट प्रोसेसिंग फीस लागू करने के प्रस्ताव को फिलहाल टालने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी विधानसभा चुनावों और देशभर में व्यापारी संगठनों के मुखर विरोध के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। यह प्रस्ताव 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी एमडीआर लगाने का था। 75,000 रुपये या अधिक के लेनदेन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रखने का प्रावधान था। हालांकि, 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट और व्यक्ति-से-व्यक्ति ट्रांसफर पर कोई शुल्क नहीं लगना था। छोटे व्यापारियों (मासिक 1 लाख रुपए तक क्यूआर कोड भुगतान) को भी एमडीआर से छूट का प्रस्ताव था। सरकार इस फैसले को 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टाल सकती है, जिसमें अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव हैं। दिवाली से पहले 15 अक्टूबर को इसे लागू करने की योजना भी टल गई थी। व्यापारी संगठनों ने नो यूपीआई डे का ऐलान कर विरोध किया था, जिसे वित्त मंत्री से बातचीत के बाद वापस ले लिया गया। एनपीसीआई छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए यूपीआई व्यापार सक्षम योजना भी चला रहा है।

वेतन वृद्धि से मांग बढ़ाएं, निजी निवेश को गति द-डीईए सचिव

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर भी दिया जोर

नई दिल्ली।

आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) की सचिव अनुराधा ठाकुर ने गुरुवार को उद्योग जगत से वेतन में ठहराव की स्थिति दूर करने का आग्रह किया। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वेतन बढ़ने से मांग को प्रोत्साहन मिलेगा और अर्थव्यवस्था के विस्तार का सकारात्मक चक्र मजबूत होगा। ठाकुर ने देश की आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के लिए निजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, यह देखते हुए कि अप्रैल से निवेश गतिविधियों में तेजी दिख रही है और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने भारत को अपनी विकास यात्रा के महत्वपूर्ण दौर में बताया, जहां सार्वजनिक-निजी भागीदारी और उद्योग, सरकार व समुदायों के बीच सहयोग से आर्थिक वृद्धि को गति मिल सकती है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का जिक्र करते हुए उन्होंने मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को इसे हासिल करने का अवसर बताया। ठाकुर ने पिछले दशक के सुधारों, जैसे जीएसटी, की सराहना की और सुधारों की प्रक्रिया जारी रखने पर जोर दिया। डीईए सचिव ने उद्योग जगत से सरकार के साथ मिलकर काम करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी, मांग बढ़ाने व कर्मचारियों की स्थिति बेहतर बनाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग का आग्रह किया। विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ठाकुर ने बताया कि अत्यधिक गरीबी 2011 के 27.1 फीसदी से घटकर 2023 में 2.6 फीसदी रह गई है, जो सरकारी प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने उद्योगों से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सरकार के साथ साझेदारी मजबूत करने का आह्वान किया।

मस्क का हुआंग को समर्थन, प्रतिभाशाली सीईओ बताया

जेनसेन हुआंग को हटाना, एन वि डिया की बड़ी भूल- उनकी जगह कोई नहीं ले सकता

ऑस्टिन ।

स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एनवीडिया के पूर्व प्रमुख जेन्सेन हुआंग के समर्थन में खुलकर बात की है, उन्हें माइकल जॉर्डन जैसा प्रतिभाशाली उद्यमी बताते हुए अपनी कंपनी में काम पर रखने तक की पेशकश कर डाली।

हालांकि, एनवीडिया का बोर्ड हुआंग को वापस लाने के किसी भी विचार के खिलाफ अडिग है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और कथित चीनी जासूस के साथ उनके संबंधों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच। मस्क ने यहां एक स्थानीय अखबार के डील बुक समिट में बोलते हुए एनवीडिया के इस कदम की तुलना शिकागो बुल्स द्वारा माइकल जॉर्डन को जीत के बीच टीम से निकाले जाने से की, और हुआंग को इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली उद्यमी सीईओ में से एक बताया। उन्होंने कहा कि हुआंग अकेले ही कई लोगों का काम संभालते हैं, सप्लाई चेन का प्रबंधन करते हैं और उनके पास दशकों के गहरे व मजबूत संबंध हैं।

मस्क ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह निश्चित रूप से हुआंग को काम पर रखेंगे, क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसके विपरीत, एनवीडिया बोर्ड ने हुआंग की बहाली की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है और एक स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है।

अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, जिनमें हाउस लीडर हकीम जेफ़रीज़ भी शामिल हैं, ने एनवीडिया के फैसले का समर्थन किया है।

जेफ़रीज़ ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए हुआंग की वापसी को अस्वीकार्य बताया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब जेन्सेन हुआंग कथित चीनी जासूस ऐलिस हुआंग के साथ अपने संबंधों को लेकर 1 दिसंबर को हाउस की तीन कमेटियों के सामने गवाही देने वाले हैं।

बोर्ड ने पूर्व प्रमुख से जुड़े विवाद के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और निर्यात नियंत्रण नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक नई समिति बनाने की भी घोषणा की है।

कृषि क्षेत्र में महिला शक्ति की भारत की गरीबी उन्मूलन में निर्णायक भूमिका

आईसीएआर का मुख्य जोर महिला सशक्तीकरण और नवाचार पर



भुवनेश्वर ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुलासा किया कि पिछले 12-13 वर्षों में भारत में 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। इस अभूतपूर्व उपलब्धि में कृषि क्षेत्र से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं का योगदान असाधारण रहा है, जिसे दुनिया में अपनी तरह का सबसे तेज और बड़ा प्रयास बताया गया है। जाट ने केंद्रीय महिला कृषि संस्थान (सीआइडब्ल्यूए) द्वारा आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय कृषि मेले को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि आईसीएआर का मुख्य जोर महिला सशक्तीकरण और नवाचार पर है। संस्थान कृषि क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित शोध के लिए समर्पित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब महिलाओं को केवल कठिन शारीरिक श्रम तक सीमित रखने के बजाय उन्हें नवाचार और कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखला, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण और विपणन शामिल है, से जोड़ने पर बल दिया जा रहा है। अे धिकारी ने बताया कि आईसीएआर शोध से जुड़ी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की दिशा में काम कर रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सब कुछ तय, बस ऐलान बाकी!

IPL 2027 में रोहित शर्मा फिर संभालेंगे MI की कमान? देख लीजिए ये पोस्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. हार्दिक पंड्या ट्रेड के जरिए टीम से बाहर हो चुके हैं और अब रोहित शर्मा की कप्तानी में वापसी की चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस बीच फ्रेंचाइजी के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इन अटकलों को और हवा दे दी है. मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें रोहित शर्मा की तस्वीर बैकग्राउंड में नजर आ रही है और उनके पीछे 'मुंबईचा राजा' लिखा है. इसका मतलब है मुंबई का राजा. फ्रेंचाइजी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'सीजन 17 मुंबईचा राजा के लिए ब्लू एंड गोल्ड में! पलटन, TATAIPL 2027 के लिए तैयार?' इस पोस्ट के सामने आते ही फैन्स ने रोहित को दोबारा कप्तान बनाने की मांग शुरू कर दी. कई फैन्स ने कमेंट में 'कैप्टन रोहित शर्मा' और 'कैप्टन रोहित शर्मा के दौर में एक बार फिर तैयार' लिखा. हालांकि, मुंबई इंडियंस ने अभी आधिकारिक तौर पर कप्तान के नाम का ऐलान नहीं किया है.

रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के सबसे सफल कप्तानों में शामिल हैं. उनकी कप्तानी में टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में कुल पांच आईपीएल खिताब जीते थे. उन्होंने 2013 से 2023 तक टीम की कप्तानी की. इसके बाद 2024 से 2026 के बीच हार्दिक पंड्या ने यह जिम्मेदारी संभाली. अब हार्दिक के टीम



से बाहर होने के बाद रोहित की कप्तानी में वापसी की संभावना जताई जा रही है.

MI ने 16 खिलाड़ियों को किया रिटेन – मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2027 के लिए रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, नमन धीर, रयान रिकेल्टन, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन डिकॉक, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, शार्दुल ठाकुर, राज बावा, मिचेल सैंटनर, अश्वनी कुमार और रघु शर्मा को रिटेन किया है. वहीं, अर्शदीप सिंह ट्रेड के जरिए टीम से जुड़े हैं. फ्रेंचाइजी ने ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एएम गजनफर, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, मोहम्मद इजहार, दानिश मालवेर, मयंक मार्कंडे, मयंक रावत, महीपाल लोमरोर, रॉबिन मिंज, रुचित अहिर और कृष्ण भगत को रिलीज किया है. हार्दिक पंड्या भी ट्रेड के जरिए टीम से बाहर हुए हैं. मुंबई इंडियंस के पास अब 32.6 करोड़ रुपये का पर्स बचा है. टीम के पास कुल 9 स्लॉट खाली हैं, जिनमें 2 विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं.

पोलार्ड बने हेड कोच, उथप्पा को भी बड़ी जिम्मेदारी – मुंबई इंडियंस ने अपने कोचिंग सेटअप में भी बदलाव किया है. वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड अब टीम के हेड कोच होंगे. भारत के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को बैटिंग कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल मैक्लेनघन को बॉलिंग कोच बनाया गया है. इसके अलावा भारतीय टीम के पूर्व फील्डिंग कोच टी दिलीप को फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी मिली है. मुंबई के अनुभवी तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी डेवलपमेंट बॉलिंग कोच के तौर पर नए कोचिंग सेटअप का हिस्सा होंगे.

सिराज को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने पर शास्त्री-गावस्कर और रहाणे ने जताई नाराजगी, बोले-यह चौंकाने वाला फैसला

वेलिंगटन, एजेंसी। भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा कि मोहम्मद सिराज के अनुभव और आक्रामकता के कारण उन्हें बेसिन रिजर्व में न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट के लिए भारत की अंतिम एकादश में जगह मिलनी चाहिए थी, और उन्होंने सवाल किया कि तेज गेंदबाज को ऐसी पिच पर क्यों बाहर रखा गया जहां सीम मूवमेंट को बढ़ावा मिलता था। रवि शास्त्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'उम्मीद है कि भारत मजबूती से वापसी करेगा। मगर अगर गति, कौशल और सीम मूवमेंट मानदंड थे और 140 क्लिक हासिल करना मुश्किल था, तो किसी को सवाल पूछना होगा। मोहम्मद सिराज कहां थे? अनुभव, आक्रामकता और गेंद के साथ कुछ करने की क्षमता। निश्चित रूप से यह कुछ मायने रखता है।' आंकड़े शास्त्री की बात का समर्थन करते हैं। सिराज वर्तमान विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र में 26.81 की औसत से 43 विकेट के साथ भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अंतिम एकादश से बाहर किए गए रवींद्र जड़ेजा भी 33 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वह भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक रहे हैं, उन्होंने 60.76 की औसत से 790 रन बनाकर रन बनाने वालों की सूची में तीसरा स्थान साझा किया है, जिसमें दो शतक और छह अर्द्धशतक शामिल हैं। शास्त्री अकेले



नहीं थे जिनका मानना ??था कि भारत ने सिराज द्वारा गेंदबाजी आक्रमण में लाए गए योगदान को नजरअंदाज कर दिया है। जैसे ही बेसिन रिजर्व में पहला दिन बीत गया, अन्य पूर्व खिलाड़ियों ने भी चयन पर सवाल उठाया। भारत के पास न्यूजीलैंड का स्कोर 70/5 था, लेकिन हेनरी निकोल्स (नाबाद 113) और ग्लेन फिलिप्स (नाबाद 94) ने 173 रनों की अटूट साझेदारी की, जिससे स्टंप्स तक मेजबान टीम का स्कोर 243/5 हो गया। यह उस तरह का स्पैल था जिसमें सफलता दिलाने में सक्षम गेंदबाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के प्रसारण पर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी सिराज के वेलिंगटन में नहीं खेलने पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि संकेत तब थे जब उन्हें 50 ओवरों की टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने केवल आखिरी गेम खेला था। दरअसल, जब उन्होंने आखिरी गेम खेला था, तो मैंने सोचा था कि वे उन्हें यहां मैच के लिए तैयार कर रहे थे। मगर अंतिम एकादश में उनका नाम न देखना एक आश्चर्य है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भारत को निराश किया है, उन्होंने कभी भी भारत को निराश नहीं किया है। उनकी गेंदबाजी में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उनकी लय अच्छी है। हमने उन्हें बीच-बीच में देखा है कि उन्होंने जो भी क्रिकेट खेला है, वह ठीक रहा है। उन्हें क्यों नहीं चुना गया यह कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। '

वेलिंगटन टेस्टः

निकोलस का शतक, फिलिप्स सैकड़े के करीब, पहले दिन न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 243 रन बनाए



वेलिंगटन, एजेंसी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जा रहे टेस्ट मैच का पहला दिन समाप्त हो गया। पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय न्यूजीलैंड ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 243 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान टॉम लैथम और डेवन कोनवे जल्दी आउट हो गए। लैथम 0 और कोनवे 4 के स्कोर पर आउट हुए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हेनरी निकोलस ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रचिन रवींद्र (15), डेरिल मिशेल (1) और विकेटकीपर-बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल (5) के विकेट गिरने से टीम की मुश्किलें बढ़ गईं। 70 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा चुकी मेजबान टीम को निकोलस और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए ग्लेन फिलिप्स ने संभाल लिया है।

प्रीमियर लीगः

मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए पोचेटिनो करेंगे डेब्यू, ऐतिहासिक उपलब्धि पर होगी आर्सेनल की नजर



नई दिल्ली, एजेंसी। प्रीमियर लीग के 11वें मैचवीक में कई बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। एनफील्ड में लिवरपूल के खिलाफ होने वाले हाई-प्रोफाइल मुकाबले में मॉरिसियो पोचेटिनो पहली बार मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर के तौर पर उतरेंगे। वहीं, न्यूकैसल यूनाइटेड के खिलाफ मैच में आर्सेनल एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने की कोशिश करेगा। अपने पहले 11 लीग मैचों में 10वीं जीत की तलाश कर रही आर्सेनल, प्रीमियर लीग के इतिहास में ऐसा करने वाली केवल पांचवीं टीम बन सकती है। इससे पहले केवल चेल्सी (2005-06), मैनचेस्टर सिटी (2011-12 और 2017-18) और लिवरपूल (2019-20) ही ऐसा कर पाई हैं। दूसरी ओर, मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में लगातार 8 मैचों से जीत नहीं पाई है, जिसमें 5 ड्रॉ और 3 हार शामिल हैं। इस सीजन में यह किसी भी टीम का सबसे लंबा बिना जीत वाला सिलसिला है। इससे पहले, क्लब को नवंबर 1989 से फरवरी 1990 के बीच ऐसे ही दौर से गुजरना पड़ा था, जब वह लगातार 11 मैचों तक कोई जीत हासिल नहीं कर पाया था।

पोचेटिनो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऐसे पहले मैनेजर बन जाएंगे, जो क्लब के साथ प्रीमियर लीग में अपना डेब्यू लिवरपूल के खिलाफ करेंगे। लिवरपूल को कोडी गैकपो से भी काफी उम्मीदें होंगी। इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने यूनाइटेड के खिलाफ प्रीमियर लीग में 5 गोल किए हैं, जो किसी भी अन्य प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ किए गए उनके गोलों से अधिक हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ अपने पिछले 3 मैचों में से हर बार उन्होंने गोल किया है।

वहीं, मैनचेस्टर सिटी अपने घरेलू मैदान पर फुलहम का सामना करेगी और लंदन के इस क्लब के खिलाफ अपनी शानदार जीत की लय को आगे बढ़ाना चाहेगी। सिटी ने सभी प्रतियोगिताओं में फुलहम के खिलाफ अपने पिछले 20 मुकाबले जीते हैं, जिसमें लगातार 17 लीग मैच भी शामिल हैं। इंग्लिश फुटबॉल में एक टीम द्वारा दूसरी टीम के खिलाफ दर्ज की गई यह सबसे लंबी जीत की लय है। हालांकि, एंजो मारेस्का की टीम (चेल्सी) को इस सीजन में अपने पिछले तीन प्रीमियर लीग मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि फुलहम अपने पिछले 4 मैचों में अजेय रही है, जिसमें उन्होंने 2 जीत हासिल की हैं और 2 मैच ड्रॉ खेले हैं। एस्टन विला में उनाई एमरी प्रीमियर लीग में 150 मैचों में टीम को मैनेज करने का मुकाम हासिल करेंगे। मार्टिन ओ'नील के बाद, ऐसा करने वाले वह विला के दूसरे मैनेजर बन जाएंगे। एमरी ने अपने पहले 149 लीग मैचों में 76 जीत, 33 ड्रॉ और 40 हार दर्ज की हैं। इस सीजन में विला के फॉरवर्ड निकोलस जैक्सन भी सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने 6 गोल किए हैं और उनसे आगे केवल एर्लिंग हालैंड (9 गोल) और अलेक्जेंडर इसाक (7 गोल) हैं। बोर्नमाउथ का सामना नॉटिंघम फॉरेस्ट से होगा, तो उनकी कोशिश पहली बार लगातार 5 टॉप-फ्लाइट मैच जीतने की होगी।

रबाडा-हार्मर का चला जादू, साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 9 विकेट से रौंदा

जोहान्सबर्ग, एजेंसी। साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 9 विकेट से रौंदा। द वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश से मिले महज 12 रनों के लक्ष्य को साउथ अफ्रीका ने एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन अपने 100/5 के स्कोर से आगे खेलते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम दूसरी पारी में 168 रन बनाकर सिमटी। टीम की ओर से लिटन दास ने 38 गेंदों में सर्वाधिक 39 रन बनाए, जबकि महफिजुल इस्लाम ने 32 रनों का योगदान दिया। हालांकि, इन दोनों को छोड़कर बांग्लादेश के बाकी बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के आगे आसानी से घुटने टेक दिए। तौहीद हिरदॉय ने 23 रन बनाए जबकि मुशफिकुर रहीम ने 22 रनों का योगदान दिया। मेहदी हसन मिराज ने 15 रन बनाए। दूसरी पारी में बांग्लादेश के पांच बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। गेंदबाजी में साउथ अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12.3 ओवर में 51 रन देकर 6 विकेट चटकाए। वहीं, पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले कगिसो रबाडा ने दूसरी इनिंग में भी 3 विकेट झटके। मार्को जानसेन ने एक विकेट अपने नाम किया।



रबाडा ने दोनों पारियों को मिलाकर कुल 8 विकेट झटके और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले, बांग्लादेश ने पहली पारी में तौहीद हिरदॉय द्वारा खेली गई 137 और लिटन दास की 120 रनों की शानदार पारियों की बदौलत 400 रन बनाए, जो टीम का टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर भी रहा। तंजीद हसन तमीम ने 67 रनों का योगदान दिया। रबाडा ने पहली पारी में 5, जबकि डेन पैटरसन ने 4 विकेट निकाले। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 557 रन बनाए। टीम की ओर से मार्क्वेस एकरमैन ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 157 रनों की लाजवाब पारी खेली।

वहीं, रयान रिकेल्टन ने 102 रन बनाए। जुबैर हमजा ने 83 और कप्तान टेंबा बावुमा ने 68 रनों का योगदान दिया। पहली पारी में गेंद से 5 विकेट लेने वाले रबाडा ने बल्ले से भी अहम योगदान दिया और 72 रनों की बेहतरीन पारी खेली। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी के आधार पर 157 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

हॉन्गकॉन्ग ओपनः

रक्षिता रामराज ने टोक्यो ओलंपिक चैंपियन को हराया, लक्ष्य सेन अगले दौर में; जानें अन्य नतीजे

हॉन्गकॉन्ग, एजेंसी। भारतीय खिलाड़ियों ने हॉन्गकॉन्ग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। महिला एकल वर्ग में रक्षिता रामराज ने टोक्यो ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई को हराया। वहीं, पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन अगले दौर में पहुंच गए। भारत की रक्षिता रामराज ने गुरुवार को हॉन्गकॉन्ग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में उलटफेर करते हुए टोक्यो ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी चीन की चेन यू फेई को सीधे गेम में हरा दिया। कोयंबटूर की 19 वर्षीय रक्षिता ने यूफेई को 21-18, 24-22 से हराकर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की यादगार जीत में से एक दर्ज की। रक्षिता का अगला मुकाबला थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग से होगा।



रक्षिता ने करियर की सबसे बड़ी जीत बताया – रक्षिता ने शुरुआती दौर में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट को भी हराकर उलटफेर किया था। मैच के बाद रक्षिता ने कहा, मुझे लगता है कि यह मेरे करियर की अब तक की सबसे बड़ी जीत में से एक है। वह मेरी सबसे बड़ी आदर्श हैं और मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उन्हें हरा दिया। यह मेरे बैडमिंटन करियर के सबसे यादगार दिनों में से एक रहेगा।

चेसः

टोटल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में अर्जुन एरिगैसी और प्रज्ञानंद ने अपने मुकाबले जीते, जानें किसे हराया

नई दिल्ली, एजेंसी। दिन में पहले, भारतीय खिलाड़ी अपने चार ब्लिट्ज गेम में से दो और एक फास्ट क्लासिक मुकाबला हार गए थे। उन्हें दो रैपिड गेम में से एक में जीत मिली, जबकि दूसरे में हार का सामना करना पड़ा। एरिगैसी अब नौवें स्थान के लिए मैच में हाइक एम. मार्टिरोसियन से भिड़ेंगे। अर्जुन एरिगैसी ने जॉर्डन वैन फॉरेस्ट को आर्मागेडन टाई-ब्रेक में हराकर टोटल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर पायलट में अपना मैच जीता। वहीं, आर. प्रज्ञानंद ने नोडिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराया। प्रज्ञानंद की जीत के साथ ही उनकी बहन



आर. वैशाली के साथ होने वाला संभावित मुकाबला टल गया। एरिगैसी ने पहले दिन का मुकाबला 11.5-8.5 से जीता था। फॉरेस्ट ने बुधवार को वापसी करते हुए दूसरे दिन 12-8 से जीत हासिल की। इससे नौवें से 12वें स्थान के लिए आर्मागेडन में एक निर्णायक मुकाबला हुआ। काले मोहरों से खेलते हुए, वैन फॉरेस्ट ने टाई-ब्रेक में ज्यादातर समय जीत की स्थिति बनाए रखी। लेकिन उन्होंने 34वें मूव पर अपना फायदा गंवा दिया। इसका फायदा एरिगैसी को मिला और भारतीय खिलाड़ी ने जीत हासिल कर ली। दिन में पहले, भारतीय खिलाड़ी अपने चार ब्लिट्ज गेम में से दो और एक फास्ट क्लासिक मुकाबला हार गए थे। उन्हें दो रैपिड गेम में से एक में जीत मिली, जबकि दूसरे में हार का सामना करना पड़ा। एरिगैसी अब नौवें स्थान के लिए मैच में हाइक एम. मार्टिरोसियन से भिड़ेंगे। आर. प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के अब्दुसत्तोरोव को हराकर 21वें स्थान के लिए मुकाबले में अपनी जगह पक्की की। फास्ट क्लासिक गेम से पहले वह 3.5-8.5 से पीछे चल रहे थे, लेकिन काले मोहरों से खेलते हुए जीत के साथ वापसी की और दिन का स्कोर 11.5-8.5 कर दिया। अब उनका सामना अभिमन्यु मिश्रा से होगा। अगर प्रज्ञानंद यह मुकाबला हार जाते, तो उन्हें 23वें और 24वें स्थान के लिए वैशाली के खिलाफ खेलना पड़ता।

2027 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगे ऐश बार्टी और शिंगो कुनिदा

नई दिल्ली, एजेंसी । चार बार की मेजर चैंपियन और पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 ऐश बार्टी को खिलाड़ी श्रेणी में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए चुना गया है। जापान के शिंगो कुनिदा, जो चार बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 50 बार के मेजर चैंपियन हैं, उन्हें 'व्हीलचेयर टेनिस कैटेगरी' में चुना गया है। इस श्रेणी में उन खिलाड़ियों को जगह दी जाती है, जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन और उपलब्धियों का रिकॉर्ड रहा हो। बार्टी तीन बार की मेजर सिंगल्स चैंपियन हैं। उन्होंने रोलैंड-गैरोस (फ्रेंच ओपन) 2019, विंबलडन 2021 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के खिताब जीते हैं। इसके अलावा, उन्होंने 2018 यूएस ओपन में अपना पहला मेजर डबल्स खिताब भी जीता था। सिंगल्स में वह 2019 में वर्ल्ड नंबर 1 बनीं। वह कुल 121 हफ्तों तक टॉप पर रहीं, जिसमें लगातार 114 हफ्ते शामिल रहे। इसके साथ ही 2019 से 2021 तक लगातार तीन साल तक वह 'ईयर-एंड नंबर 1' (साल के अंत में नंबर 1) रहीं।

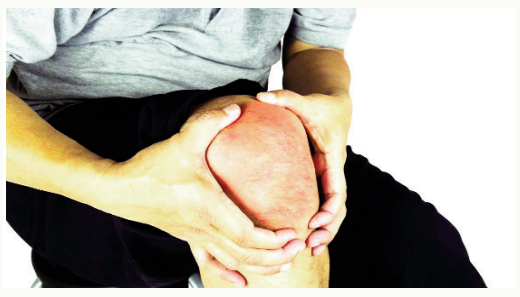
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीतने के बाद, जब वह वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर थीं, तब उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया था। वह इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली 35वीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बनेंगी और 2013 के बाद यह सम्मान पाने वाली



पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला होंगी। बार्टी ने कहा, 'मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के उन महान खिलाड़ियों को देखने का मौका मिला, जिन्होंने इस खेल को नई दिशा दी और बहुत गर्व के साथ हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया। उनके साथ मेरा नाम लिया जाना एक अद्भुत अहसास है। मेरा करियर एक 'टीम एफर्ट' (सामूहिक प्रयास) था, इसलिए यह सम्मान मेरे परिवार, मेरे कोचों और उन सभी लोगों का भी है, जिन्होंने इस सफर में मेरी मदद की। ' वहीं, शिंगो कुनिदा इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जापान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वह इतिहास के सबसे सफल पुरुष व्हीलचेयर टेनिस खिलाड़ी हैं, जिनके नाम रिकॉर्ड 28 मेजर सिंगल्स खिताब और कुल 50 मेजर खिताब दर्ज हैं। चार बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता शिंगो 'करियर गोल्डन स्लैम' पूरा करने वाले पहले पुरुष व्हीलचेयर टेनिस खिलाड़ी बने और उन्होंने रिकॉर्ड 582 हफ्तों तक विश्व नंबर 1 सिंगल्स रैंकिंग अपने नाम रखी। 2010 में हॉल ऑफ फेम द्वारा इस श्रेणी को शामिल किए जाने के बाद से कुनिदा इसमें जगह पाने वाले आठवें व्हीलचेयर टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। बार्टी और कुनिदा को यह खबर हॉल ऑफ फेम के सह-अध्यक्ष किम क्लाइस्टर्स और पैट्रिक मैकेनरो द्वारा किए गए सरप्राइज वीडियो कॉल के जरिए मिली।

खेल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में उनकी जगह को सम्मान देते हुए इस वीडियो कॉल में हॉल ऑफ फेम के लगभग 20 अन्य सदस्य भी शामिल हुए। ट्रेसी ऑस्टिन, जिम कूरियर, रोजर फेडरर, मार्टिना नवरातिलोवा, पैट राफ्टर, पैम श्राइवर, एस्टर वर्गीर और अन्य हॉल ऑफ फेम सदस्यों ने उन्हें बधाई संदेश दिए और आधिकारिक तौर पर इस खास क्लब में उनका स्वागत किया।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1



बदलते मौसम भयानक हो सकता है जोड़ों का दर्द, इन आसान तरीकों से अभी से करें बचाव

मौसम में धीरे-धीरे बदलाव आने लगा है। बदलते मौसम में अक्सर जोड़ों में जकड़न, दर्द या सूजन की शिकायत बढ़ जाते हैं। ठंड के मौसम की शुरुआत भी होने लगी है। यह समस्या बदलते मौसम में ज्यादा बढ़ जाती है। आयुर्वेद में बताया है कि जब शरीर में वात दोष बढ़ता है, तो वह जोड़ों में सूखापन और कठोरता पैदा करता है। इसी वजह से कई लोगों को गठिया या जोड़ों दर्द की पुरानी तकलीफ पैदा हो जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, सर्दी या नमी वाले दिनों में शरीर की ऊष्मा कम हो जाती है, जिससे रक्त प्रवाह धीमा पड़ने लगता है। जिस वजह से जोड़ों में जकड़न और सूजन बढ़ जाती है। हल्का दर्द अचानक तीव्र हो जाता है।

जोड़ों के दर्द से राहत देंगी ये आयुर्वेदिक उपाय

- जोड़ों के दर्द से आराम पाने के लिए सुबह गुनगुने तिल या सरसों के तेल से जोड़ों की हल्के मालिश करें।
- नहाने से पहले शरीर पर तेल की मालिश करें और रक्त संचार भी बेहतर होता और मांसपेशियां की जकड़न कम हो जाती है।
- सर्दियों के दौरान नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, इस दौरान ठंडे पानी से नहाने बचना जरुरी है।
- भोजन में अदरक, हल्दी, लहसुन और मेथी शामिल करें। इन सभी चीजों में नैचुरल सूजनरोधी गुण होते हैं।
- ज्यादा देर बैठे या खड़े न रहें, बीच-बीच में एक्सरसाइज करें।

नहीं जमती दूध में मोटी मलाई तो ये टिप्स करेंगे आपका काम आसान

हर घर में दूध रोज आता है लेकिन दूध पर जमने वाली मोटी मलाई का भी लोग कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। जितनी मलाई मोटी होगी उतनी ही खाने में भी स्वाद लगेगी। इसके अलावा मलाई से बहुत से लोग घर में घी भी निकालते हैं। दूध की मलाई जितनी मोटी होगी उतना ही घी अच्छी क्वालिटी का होगा। लेकिन बहुत सी महिलाओं की शिकायत होती है कि उनके दूध से मलाई अच्छी तरह से नहीं जम पाती। ऐसे में आपको आज कुछ ऐसे आसान टिप्स बताते हैं जिनके जरिए आप घर के दूध से मोटी मलाई निकाल सकते हैं...

धीमी आंच पर उबालें दूध

ज्यादातर घरों में दूध को मीडियम और फुल फ्लेम पर ही गर्म किया जाता है। परंतु यदि आप दूध में से मोटी मलाई जमाना चाहते हैं तो दूध को 5-10 मिनट के लिए धीमी आंच पर उबालें।

उबाल आते न बंद करें गैस

दूध में उबाल आते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि गैस को एकदम से बंद न करें। दूध को उबालने के बाद कुछ मिनट के लिए कम आंच पर उबालें। इसके बाद ही गैस बंद करें। इस तरीके से भी दूध में मोटी मलाई जमेगी।

जाली से ढकें दूध

दूध को उबालने के बाद पूरी प्लेट से दूध को ढकने की जगह आप जाली से दूध को ढकें। इस तरीके से दूध आसानी से ठंडा भी होगा और उसमें मलाई भी मोटी जमेगी। पूरी प्लेट से दूध को ढक देने से भाप अच्छे से नहीं निकल पाती जिसके कारण मलाई भी मोटी नहीं जम पाती। ऐसे में आप दूध को जाली से ही ढकें।

सामान्य तापमान

दूध को सामान्य तापमान पर ठंडा करना आवश्यक है। गर्म दूध को फ्रिज में बिल्कुल भी न रखें। ठंडा दूध होने पर बर्तन को बिना हिलाए-जुलाए धीरे से फ्रिज में रखें। इससे दूध में मलाई मोटी जमेगी।

मलाई को निकालकर करें दूध का इस्तेमाल

दूध को जब भी इस्तेमाल करना है तो पहले उसमें जमी पूरी मलाई को निकाल लें। इसके बाद ही दूध का इस्तेमाल करें। इससे दूध में मलाई जमी रहेगी और बार-बार दूध का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं।





मुंह की बदबू से लेकर मसूड़ों की सूजन तक, अमरूद के पत्तों में छिपा है हर समस्या का राज

आज के समय में अधिकतर लोगों को छाले, मसूड़ों में सूजन, दांतों में दर्द और मसूड़ों से खून आने जैसी ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसकी वजह से कई लोग परेशान रहते हैं। हालांकि इस समस्या से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों में से एक और औषधीय गुणों से भरपूर अमरूद के पत्ते लाभकारी माने जाते हैं। अमरूद के पत्तों से बने माउथ वॉश का इस्तेमाल करने से मुंह की कई समस्याओं से राहत मिल सकती है।

बता दें कि अमरूद के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल गुए पाए जाते हैं। जोकि मुंह के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से राहत के लिए अमरूद के पत्तों से माउथ वॉश कैसे बनाएं और इससे क्या फायदे मिलते हैं।

अमरूद के पत्तों का माउथवॉश

इसके लिए एक गिलास पानी में 4-5 अमरूद के पत्ते, 1/4 छोटी चम्मच नमक और 2-3 लौंग डालकर इसको तब तक उबालें, जब तक पानी आधा न रह जाए। फिर इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल मिला दें। अब इस माउथ वॉश से कुल्ला करें।

माउथ वॉश के फायदे

एक्सपर्ट के मुताबिक अमरूद के पत्तों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके पत्तों का माउथवॉश का इस्तेमाल करने से मुंह का स्वास्थ्य दुरुस्त होने के साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं।

मुंह की बदबू से राहत

अमरूद के पत्तों और लौंग में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इस माउथ वॉश का इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया खत्म होती है और मुंह की बदबू से भी राहत मिलती है। इसका इस्तेमाल करने से फ्रेश फील होता है।

छालों से दे राहत

बता दें कि अमरूद के पत्तों में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ऐसे में इस माउथ वॉश का इस्तेमाल करने से मुंह के संक्रमण से बचाव होता है और छालों की समस्या से भी राहत मिलती है। वहीं इस माउथ वॉश के इस्तेमाल से मुंह के पीएच को बैलेंस रखने में सहायता मिलती है।

कैविटीज से बचाव

इस नेचुरल माउथ वॉश के इस्तेमाल से दांतों के दर्द को कम करने, कैविटीज से बचाव करने, दांतों के पीलेपन को कम करने और इनको हेल्दी बनाए रखने में सहायता मिलती है।

मसूड़ों की मजबूती

अक्सर लोगों को मसूड़ों में ब्लीडिंग और सूजन होने की समस्या से परेशान रहते हैं। ऐसे में इस नेचुरल माउथ वॉश का इस्तेमाल करने से मसूड़ों की सूजन कम होती है। साथ मसूड़ों को टाइट कर मजबूती देने, ब्लीडिंग से बचाव करने और इंफेक्शन से बचाव करने में सहायता मिलती है।

दांतों होंगे हेल्दी

अमरूद के पत्ते, लौंग और नारियल तेल से बना माउथ वॉश से दांतों को मजबूती मिलती है। इससे दर्द और सूजन भी कम होती है। साथ ही इस माउथ वॉश के इस्तेमाल से दांतों को नेचुरली साफ करने में मदद मिलती है।

पुरानी से पुरानी खांसी और जमे कफ को बाहर निकाल देगा ये देसी नुस्खा, सर्दियों में बेहद फायदेमंद



अक्टूबर का महीना खत्म होते-होते ठंड ने दस्तक दे दी है। यह मौसम जितना सुहावना होता है, उतनी ही परेशानियां भी साथ लाता है। खासकर खांसी, जुकाम और सीने में जमे कफ की समस्या लगभग हर घर में देखने को मिलती है। कई बार दवाइयां लेने के बाद भी इन समस्याओं से राहत नहीं मिलती। ऐसे में आयुर्वेदिक और देसी नुस्खे बेहद असरदार साबित हो सकते हैं।

अपनाएं ये देसी नुस्खा

पुरानी खांसी और जमे हुए कफ को निकालने के लिए यह नुस्खा बेहद कारगर है। इसके लिए सबसे पहले एक नींबू को धीमी आंच पर करीब 20 मिनट तक गर्म करें। इसके बाद उसे बीच से काट लें। अब एक चम्मच में आधा चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच अदरक का रस, एक चम्मच शहद और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करें। इसे धीरे-धीरे चाटें। इस घरेलू मिश्रण का म्युकोलिटिक ऐक्शन सीने में जमा हुए कफ को ढीला करता है और पुरानी से पुरानी खांसी से राहत दिलाता है।

सर्दियों में इन बातों का रखें ध्यान

संक्रमण से बचाव

सर्दियों के मौसम में संक्रमण (इंफेक्शन) का खतरा काफी बढ़ जाता है। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। समय-समय पर हाथ धोते रहें, और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से पहले मास्क पहनें। जिन लोगों की इम्युनिटी कमजोर होती है, उन्हें ठंड के मौसम में खास सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को बार-बार खांसी-जुकाम और सर्दी से जुड़ी समस्याएं घेर सकती हैं।

रोज पिएं हल्दी वाला दूध

सर्दियों के मौसम में हर रात सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना बेहद फायदेमंद माना जाता है। हल्दी में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की इम्युनिटी को बूस्ट करते हैं और आपको खांसी, जुकाम तथा गले की खराश जैसी मौसमी समस्याओं से बचाते हैं। यह न केवल शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है, बल्कि सर्द मौसम में गर्माहट भी बनाए रखता है।

पौष्टिक आहार लें

सर्दियों के मौसम में शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार का सेवन बेहद जरूरी है। अपने दैनिक भोजन में हरी सब्जियां, दालें, मौसमी फल और घर का बना ताजा खाना शामिल करें। इससे शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। इस मौसम में जंक फूड, तली-भुनी या बहुत मसालेदार चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये पाचन को प्रभावित कर सकती हैं और सर्दी-जुकाम की समस्या बढ़ा सकती हैं।

यह नुस्खा सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। अगर आपको लगातार खांसी या सीने में दर्द जैसी समस्या है, तो किसी योग्य चिकित्सक या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

रात भर मुंह में रखकर सोएं तुलसी का पत्ता, मिलेंगे गजब स्वास्थ्य लाभ

तुलसी का भारतीय घर में धार्मिक महत्व तो है ही लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक औषधि भी है। आज भी हमारी दादी मां- नानी मां भी सर्दी- खांसी या कोई भी वायरल होने पर तुलसी का काढ़ा आदि पीने की सलाह देती हैं। बता दें तुलसी की पत्तियों में एंटी-बैक्टीरियल, एंटा- सेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद की मानें तो ये कई बीमारियों का इलाज है।

पाचन तंत्र होता है बेहतर

अगर आपको गैस और एसिडिटी की दिक्कत रहती है, तो रोजाना मुंह में तुलसी के 2 पत्ते रखकर सोएं। इससे पाचन तंत्र स्ट्रांग बनेगा।

तनाव से मुक्ति

तुलसी की पत्तियों में भरपूर मात्रा में अडैप्टोजेन होता है, जो स्ट्रेस लेवल को कम करने में मददगार है। तुलसी की पत्तियां नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती हैं। इसे खाकर सोने से मन शांत होता और बेहद पॉजिटिव महसूस होता है।

सिर दर्द होता है गायब

सर्दी- जुकाम से मिलती है राहत

तुलसी की पत्तियों में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो वायरस का जड़ से खत्म कर देते हैं। रातभर इन्हें मुंह में रखकर सोने से सर्दी-जुकाम से राहत मिलती है।



अगर आपको लगातार सिर में दर्द रहता है और इस वजह से नींद भी नहीं आती है तो अपने मुंह में पत्ते रखकर सोएं। इसमें मौजूद गुण सिर के दर्द को कम करते हैं।

ब्लड शुगर रहता है कंट्रोल में

जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उन्हें तुलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन बढ़ता है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है।

इम्यूनिटी होता है बूस्ट

तुलसी की पत्तियों में मौजूद विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। रोजाना इसे मुंह में रखकर सोने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।

चेहरे पर कैसे लगाएं मुल्तानी मिट्टी? इस तरह मिलेंगे बेहतर रिजल्ट्स

चेहरे की खूबसूरती और नेचुरल ग्लो बढ़ाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कई लगो करते हैं। यह स्किन से ऑयल और गंदगी हटाकर उसे साफ, मुलायम और फ्रेश बनाती है।

चेहरे पर चमक बनाए रखने के लिए लोग तरह-तरह की चीजों का उपयोग करते हैं। कई लोग मार्केट से महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स खरीदकर उपयोग करते हैं, तो कुछ लोग घर में ही मौजूद चीजों को लगाते हैं। ऐसे में अगर आप भी स्किन को मुलायम और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं।

मुल्तानी मिट्टी को चेहरे पर लगाने से कई तरह के फायदे होते हैं। इसका फेस पैक स्किन को गहराई से साफ करता है और चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल भी करता है।



हालांकि, कई बार लोग इसका गलत तरीके से उपयोग कर लेते हैं, जिससे स्किन ड्राई या रफ हो सकती है। अगर आप भी अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें।

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने का तरीका

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने के लिए सबसे पहले चेहरे को सही से साफ कर लें, ताकि स्किन के पोर्स खुल जाएं और गंदगी साफ हो सके। अब आप एक बाउल में दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें और इसमें अपनी स्किन टाइप के मुताबिक कुछ चीजें मिला लें। आप इसके लिए किसी डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं।

अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप मुल्तानी मिट्टी के साथ दूध या गुलाबजल का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो इसके साथ आप नींबू का रस या एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकते हैं। वहीं, नॉर्मल स्किन के लिए साफ पानी या दही बेहतर होता है।

चेहरे पर कैसे लगाएं मुल्तानी मिट्टी

मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक तैयार करने के बाद आप किसी मुलायम ब्रश या फिर उंगलियों की मदद से इसे चेहरे पर समान रूप से लगाएं। अब इसे करीब 10-15 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद इसे साफ पानी से धो लें। चेहरे से फेस पैक हटाने के बाद कोई हल्का मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। इससे त्वचा में नमी बनी रहती है।



Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भाखड़ा नहर पर पुल ढहा, दो ट्रक फंसे, भीषण आग

पटियाला , एजेंसी। पंजाब के पटियाला में गुरुवार सुबह भाखड़ा नहर पर बना एक पुल ढह गया। हादसे में दो ट्रक पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से में फंस गए, जिसमें से एक में भीषण आग लग गई। हालांकि, गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना सुबह करीब छह बजे पटियाला-संगरूर बायपास (एनएच-07) पर हुई। करीब 60 मीटर लंबा स्टील ट्रस पुल अचानक ढह गया, जिससे बालू से भरा एक ट्रक और दूसरा ट्रक बीच में ही अटक गए। एक ट्रक चालक सुखविंदर सिंह ने बताया कि दूसरे ट्रक के फंसते ही उन्होंने अपना वाहन रोकने का प्रयास किया, जिससे उनके पैर में मामूली चोट आई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमों ने आग पर काबू पाया और पुलिस ने स्थिति संभाली। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रभावित मार्ग पर यातायात को तत्काल मोड़ दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बताया कि वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बाईं ओर के यातायात को सर्विस रोड पर मोड़ा गया है। घटनास्थल पर चौबीसों घंटे सुरक्षा कर्मी, संकेतक और रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। पुल ढहने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन स्थानीय निवासियों के अनुसार, पुल पहले भी हिलता था और इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई थी। स्थानीय निवासी पवन कुमार ने पुल को करीब एक दशक पुराना बताया। एनएचएआई के अनुसार, चार लेन वाले पटियाला बायपास खंड को 2018 में उसे सौंपा गया था और अब यह मार्ग उसके अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध के तहत है। दुर्घटनाग्रस्त पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने पंजाब लोक निर्माण विभाग की निगरानी में किया था। भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) के जिला अध्यक्ष अवतार सिंह भी घटना की सूचना मिलते ही मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचे।

गोधरा कांड के सात दोषियों की पैरोल तीन सप्ताह बढ़ी

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों की पैरोल तीन सप्ताह बढ़ाने का आदेश दिया है। इन दोषियों को इसी वर्ष जून-जुलाई में चार महीने की पैरोल दी गई थी। अवधि बढ़ाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि दोषियों ने अपनी सजा में छूट यानी रिमिशन के लिए राज्य सरकार के समक्ष आवेदन किया है, लेकिन उन पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि रिमिशन की अर्जियां अभी विचाराधीन हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सजा माफी की अर्जियों पर निर्णय में देरी होना दोषियों की गलती नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने सातों दोषियों की पैरोल अवधि तीन सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया। मामले में आगे की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर लंबित रिमिशन अर्जियों के निर्णय पर निर्भर करेगी।

कोर्ट ने घर की कुर्की का दिया आदेश, नगीना सांसद को झटका

गाजियाबाद , एजेंसी। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ा झटका लगा है। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर को सुनवाई में पेश नहीं होने पर सख्त रुख अपनाते हुए उनके घर की कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। यह मामला साल 2018 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान हुई मारपीट और गाली-गलौज से जुड़ा है, जिसकी शिकायत धर्मेंद्र कुमार ने की थी। इससे पहले, इसी अदालत ने सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। 17 नवंबर को उन्हें अदालत में मौजूद रहने को कहा गया था, ताकि उनके खिलाफ आरोप तय किए जा सकें। हालांकि, वह एक बार फिर गैरहाजिर रहे। बताया गया कि चंद्रशेखर आजाद मुंबई में संसदीय कार्यसमिति की पूर्व निर्धारित बैठक में शामिल होने के कारण अदालत नहीं पहुंच सके। उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र भी दिया था। लेकिन, अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। फिलहाल, अपने खिलाफ आए इस आदेश पर चंद्रशेखर आजाद की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

योगी का सपा पर वार: गुंडे-माफिया कभी सीधे नहीं हो सकते



लखनऊ , एजेंसी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर रोड शो के दौरान हुई 14 वर्षीय मासूम आर्यवर्धन सिंह की मौत को लेकर कड़ा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने सपा को माफिया पोषक करार देकर कहा कि गुंडे-माफिया कभी सीधे नहीं हो सकते और उन्हें केवल डंडे से ही सीधा किया जा सकता है, जो काम उनकी सरकार कर रही है। सीएम योगी ने अपनी बात को बल देकर एक तीखी तुलना की। उन्होंने कहा, जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरह सपा के गुंडे-माफिया कभी सीधे नहीं हो सकते। इन्हें डंडे से ही सीधा किया जा सकता है। उन्होंने सपा के रोड शो में व्याप्त अराजकता पर सवाल उठाकर कहा कि उनकी सरकार ने बेहतर सड़कें माफिया पोषक पार्टी के गुंडों को अराजकता फैलाने के लिए नहीं बनवाई हैं, बल्कि विकास और सुशासन के लिए बनाई हैं।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर हरी नाराजगी जाहिर की कि दुर्घटना के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना के दो शब्द भी नहीं कहे। उन्होंने भावुक होकर पूछा, आखिर उस होनहार मासूम आर्यवर्धन की गलती क्या थी? योगी ने घोषणा की कि वह स्वयं पीड़ित परिवार के घर जाएंगे और उन्हें हर हाल में न्याय दिलाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी कीमत पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और माफियापोषक पार्टी के गुंडों को उनकी सही जगह दिखाई जाएगी।
अपने निर्धारित कार्यक्रमों के तहत, मुख्यमंत्री योगी ने इससे पहले वानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, जहां वनमंत्री अरुण कुमार ने विश्वविद्यालय का नाम ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के नाम पर रखने की घोषणा की। इस कार्यक्रम के उपरांत, योगी आदित्यनाथ टाउनहॉल में जनचौपाल लगाएंगे और इसके बाद वे आर्यवर्धन के घर जाकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाएंगे।

झारखंड में इबोला को लेकर अलर्ट, अस्पतालों को 24 घंटे स्क्रीनिंग के निर्देश

रांची, एजेंसी। झारखंड में इबोला वायरस के संभावित खतरे को देखकर राज्य की हेमंत सोरोन सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। हालांकि, अब तक राज्य में इबोला संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और रिम्स, मेडिकल कॉलेजों, सदर अस्पतालों सहित सभी स्वास्थ्य संस्थानों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। मंत्री अंसारी ने अस्पतालों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। संदिग्ध मरीज मिलने पर तत्काल रिपोर्टिंग, जांच, आइसोलेशन और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, पीपीई किट और जरूरी चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता के साथ स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण से बचाव का प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ाने तथा राज्य के सभी 24 जिलों में 24 घंटे स्क्रीनिंग और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। इससे पहले 12 नवंबर को रांची स्थित रिम्स में इबोला से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इबोला के लक्षण संक्रमण के 2 से 21 दिनों के भीतर दिखाई दे सकते हैं। इनमें तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, उल्टी और दस्त शामिल हैं। गंभीर स्थिति में रक्तस्राव भी हो सकता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खून और शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है, हवा से नहीं। मंत्री ने लोगों से घबराने और अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय सतर्क रहने तथा लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की अपील की।

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम जमानत बरकरार

● आजम ने कहा- देश आजाद है, लेकिन संविधान कैद

लखनऊ, एजेंसी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने से इंकार किया है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी है और वह इसमें दखल नहीं देगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे की सुनवाई इस आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना की जाए। आजम को मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, इसके खिलाफ ईडी बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची और तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी ने गिरफ्तारी के आधार की जानकारी ने देने के आजम के दावे को गलत बताया। हालांकि, ईडी के जल्द सुनवाई के अनुरोध पर जस्टिस जोयमाल्या बागची ने टिप्पणी की थी कि अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहते हैं, तब कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करने का फैसला किया था। इसके पहले आजम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा हुए। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा पर रोक लगने के बाद उनकी रिहाई के दौरान हुई। रामपुर पहुंचने पर आजम ने अपनी रिहाई पर खुशी जताकर कहा कि उनका यह यकीन मजबूत हुआ है कि देश आजाद है, लेकिन संविधान कैद है। हम सभी को मिलकर संविधान की आजादी की मांग करनी चाहिए। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अगर मुर्गी, बकरी और भैंस चोरी करने वाला व्यक्ति ईडी का आरोपी हो सकता है और विश्वविद्यालय बना सकता है, तब उनकी अल्लाह से दुआ है कि हर गली में एक मुर्गी चोर पैदा हो ताकि वह विश्वविद्यालय बना सके।



मोदी भी जेल में होते... लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ जांच बंद करवा दी

पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली का सनसनीखेज दावा

नई दिल्ली , एजेंसी । पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यूपीए सरकार के दौरान हुई एक जांच को लेकर सनसनीखेज दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर के ही कुछ नेताओं ने उस जांच को रुकवा दिया था, इसकी कीमत कांग्रेस आज चुका रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने 17 नवंबर को बेंगलुरु में यह बात कहकर राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने बताया कि जब वे कानून मंत्री थे (मई 2009-मई 2011), तब वर्तमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को गुजरात से बाहर किया गया था और वे जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। मोइली के अनुसार, इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी आती और उन्हें भी राज्य से बाहर कर दिया जाता। लेकिन यह पार्टी के भीतर की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थीं, इसकारण पीएम मोदी के खिलाफ चल रही जांच को हमारी अपनी ही सरकार ने रुकवा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने स्पष्ट किया कि यह फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि कुछ अन्य नेताओं के कारण हुआ था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली के दावे का संदर्भ शाह से जुड़े सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले से है। सीबीआई ने 2010 में अमित शाह को मामले में गिरफ्तार किया था, तब वे गुजरात के गृह राज्यमंत्री थे। सोहराबुद्दीन शेख एक गैंगस्टर था जिसकी 26 नवंबर 2005 को गुजरात के अहमदाबाद में एक एनकाउंटर में मौत हुई थी। हालांकि, मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 30 दिसंबर 2014 को शाह को मामले में आरोप-मुक्त कर दिया था।
मोइली ने फिलहाल इस मामले की विस्तृत जानकारी देने या उन कांग्रेस नेताओं के नाम उजागर करने से इंकार किया है, जिन पर उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इस बयान ने कांग्रेस के भीतर और राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली के दावे पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया देकर कहा है कि मोइली जैसे शक्तिशाली मंत्री रहे लोगों के पास इतिहास के बहुत सारे साक्ष्य हो सकते है। उन्होंने गुजरात में एसआईटी के गठन और क्लीन चिट जैसे घटनाक्रमों का जिक्र कर कहा कि इतिहास निरंतर मूल्यांकन करता है और अपने को रिवाइज भी करता है। मोइली का यह बयान तब आया है जब कांग्रेस आगामी चुनावों की तैयारियों में जुटी है, और इस बयान ने कांग्रेस पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।



संघ प्रमुख भागवत का दौरा मणिपुर में शांति बहाल करने में ठोस योगदान दे पाएगा

अब फिर आश्वासन देने की जरूरत नहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता ने उठाए सवाल

इम्फाल , एजेंसी। मणिपुर में कांग्रेस विधायक दल के नेता केशम मेघचंद्र सिंह ने सवाल उठाया है कि क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत का मौजूदा दौरा इस हिंसाग्रस्त राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में कोई ठोस योगदान दे पाएगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर को अब एक बार फिर आश्वासन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे ''स्थायी शांति, सुरक्षा, पुनर्वास, जवाबदेही और एक विश्वसनीय राजनीतिक रोडमैप की जरुरत है।'' भागवत तीन दिवसीय दौरे पर इंफाल पहुंच गए हैं। इस दौरान वह राज्य में संगठन की गतिविधियों और सामाजिक पहलों की समीक्षा करेंगे।
संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि भागवत आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत राज्य में चलाए जा रहे कार्यक्रमों का आकलन करेंगे। केशम ने पोस्ट में कहा कि मणिपुर को शांति चाहिए, केवल संगठनात्मक बैठकें नहीं। भागवत का 18 से 20 नवंबर तक मणिपुर दौरा हमारे राज्य में जारी संकट को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य लंबे समय से जातीय संघर्ष झेल रहा है। इस दौरान निर्दोष लोगों की जान गई, हजारों परिवार विस्थापित हुए, घर और आजीविका के साधन नष्ट हो गए और कई समुदायों के बीच खाई और गहरी हो गई है।
उन्होंने सवाल किया कि संघ प्रमुख भागवत का यह दौरा मणिपुर में स्थायी शांति बहाल करने में क्या ठोस योगदान देगा? क्या आरएसएस नेतृत्व हिंसा से प्रभावित विस्थापित परिवारों और समुदायों से सीधे बातचीत करेगा? सिंह ने यह भी पूछा कि क्या मेइती, कुकी-जो और नगा समुदायों के बीच विश्वास बहाली और मेल-मिलाप को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि क्या आरएसएस नेतृत्व लंबे समय से जारी इस संकट के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले राजनीतिक तंत्र की जिम्मेदारी पर भी बात करेगा?'' उन्होंने कहा कि संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा और शताब्दी समारोह आरएसएस के आंतरिक एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन मणिपुर के लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिंह ने कहा कि राज्य को अब और आश्वासनों की जरूरत नहीं है। उसे स्थायी शांति, सुरक्षा, पुनर्वास, जवाबदेही और एक विश्वसनीय राजनीतिक कार्ययोजना चाहिए।



उन्होंने कहा कि यदि आरएसएस नेतृत्व का बीजेपी के राजनीतिक नेतृत्व पर प्रभाव है, तो मणिपुर के लोगों को यह उम्मीद करने का पूरा अधिकार है कि उस प्रभाव का इस्तेमाल शांति, मेल-मिलाप और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाने में किया जाएगा। मई 2023 में घाटी में रहने वाले मेइती और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 लोग अब भी लापता हैं। इस संघर्ष के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इस साल फरवरी से पहाड़ी जिलों में कुकी और नगा समुदायों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है।

चक्रवात अकवान का खतरा: ओडिशा में 80 हजार से अधिक लोग सुरक्षित निकाले गए



भुवनेश्वर , एजेंसी। ओडिशा सरकार ने चक्रवात 'अकवान' के आसन्न खतरे को देखकर अब तक 80 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। ओडिशा राज्य में 74 बचाव दल तैनात किए गए हैं और एहतियात के तौर पर कई जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। जिला अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' शुक्रवार दोपहर तक उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों के बीच, नरसापुर (आंध्र प्रदेश) और पुरी (ओडिशा) के पास गोपालपुर के पूर्व में दस्तक दे सकता है। इस दौरान हवा की अधिकतम निरंतर गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहने और झोंकों की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। गुरुवार सुबह यह आंध्र प्रदेश के नरसापुर से करीब 440 किलोमीटर और ओडिशा के गोपालपुर से 530 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में केंद्रित था और बीते छह घंटों के दौरान 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है।
ओडिशा के तटीय और दक्षिणी इलाकों में बुधवार रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जिसकी तीव्रता धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है। ओडिशा सरकार ने कुल दो लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। चक्रवात से गंजाम जिले के सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है, जहां गुरुवार सुबह तक 36,398 लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों में पहुंचाया जा चुका था। जिले में 308 राहत केंद्र संचालित हैं, जहां विस्थापित लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, गंजाम में 1,098 गर्भवती महिलाओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की टीमें मलकानगिरि, कोरापुट, गंजाम, पुरी सहित विभिन्न संवेदनशील जिलों में तैनात की गई हैं।
मौसम विभाग ने केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजाम, गजपति और कंधमाल जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि समुद्र में उठने वाली लहरों के कारण गंजाम और पुरी के निचले इलाकों में 0.5 से एक मीटर तक पानी भर सकता है। चक्रवात के आगे बढ़ने के साथ दक्षिण और उत्तर ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है, जिनकी रफ्तार फिलहाल 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे है और झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है।

सोनिया गांधी नागरिकता मामला की सुनवाई 27 को

नई दिल्ली, एजेंसी । राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ दायर निजी शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उस समय तक उन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल नहीं की थी। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की है। इसी दिन पुलिस की ओर से दाखिल की जाने वाली रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। शिकायत सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने दायर की है। उन्होंने सोनिया गांधी पर कथित तौर पर जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग की है। अदालत अब पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही पर विचार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी, कांग्रेस और आप सहित कई दलों को नोटिस भेजे

नई दिल्ली, एजेंसी । सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को लेकर एक अहम कदम उठाया है। व्यापारियों द्वारा दायर एक याचिका के बाद, अदालत ने अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) सहित कई राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। व्यापारियों का तर्क है कि अगर प्रदर्शनों के लिए रामलीला मैदान की अनुमति दी जाती है, तो उनके व्यापार करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। व्यापारी पहले भी कांग्रेस के 1 नवंबर को हुए प्रदर्शन को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इस बेंच में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना भी शामिल थीं। बेंच ने इससे पहले व्यापारी संगठनों से इन आंदोलनकारी समूहों को पक्षकार बनाने के लिए कहा था। 3 नवंबर को सीजेआई ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। बुधवार को अदालत ने स्पष्ट किया कि विरोध करने के अधिकार और व्यवसाय चलाने के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित होना बेहद ज़रूरी है। सीजेपी, आप और कांग्रेस के अलावा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन को भी नोटिस मिला है, जिसकी प्रमुख नेहा बोरा हैं। नेहा बोरा अक्सर कांग्रेस और सीजेपी दोनों के प्रदर्शनों में प्रमुख रूप से नजर आती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की संशोधित याचिका पर दिए गए हैं। व्यापारियों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में अपनी दलीलें रखीं। बेंच ने कहा कि नई जोड़ी गई रिट याचिका को रिकॉर्ड पर लिया गया है और नए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदर्शनकारियों के विरोध करने का अधिकार और दूसरों के मौलिक अधिकार, जैसे कि व्यापार करने का अधिकार, दोनों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। रोहतगी ने अपनी दलील में बताया कि रामलीला मैदान के पास की थोक मंडियों में विरोध प्रदर्शनों के कारण कारोबारी गतिविधियां बाधित होती हैं। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शन के लिए अधिसूचित स्थानों में से एक के रूप में क्यों रखा गया है, जबकि यह व्यावसायिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका में 27 ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से निकालने पर लगी रोक

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की संघीय अपीलीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन को 27 से अधिक ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर करने से रोक दिया है। अदालत ने मंगलवार को पेंटागन की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें फैसले पर रोक लगाने की अपील की गई थी। तीन जजों की पीठ ने 2-1 से यह फैसला सुनाया। इससे पहले जून में अदालत ने माना था कि ट्रांसजेंडर सैनिकों को उनकी लैंगिक पहचान के आधार पर बाहर करने की नीति गलत है। हालांकि, इस फैसले से नए ट्रांसजेंडर सैनिकों की भर्ती का रास्ता नहीं खुला है। मामला दोबारा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है।

आयरलैंड के एयरपोर्ट पर कुल्हाड़ी से अमेरिकी सैन्य विमान तबाह

डबलिन , एजेंसी। आयरलैंड के शैनन एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति ने अमेरिकी सैन्य विमान को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक, 48 वर्षीय दाइथी ओ 'कोरेन ने अप्रैल में एयरपोर्ट की सुरक्षा घेराबंदी तोड़कर सी-130 हरक्यूलिस विमान में घुसपैठ की थी। उसने विमान की हाइड्रोलिक लाइनें काटीं, कॉकपिट के उपकरण तोड़े और ईंधन टैंक में धातु के गोले डाल दिए। करीब 60 मिलियन डॉलर का यह विमान अब उड़ान भरने लायक नहीं बचा है। आरोपी पर अमेरिकी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। दोषी साबित होने पर उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है।

इस्राइल की संसद को मिला नया स्पीकर

येरुशलम, एजेंसी। इस्राइल की संसद ने मंगलवार को मातान कहाना को नया स्पीकर चुन लिया। उन्हें 120 सदस्यीय संसद में 66 वोट मिले, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन वाले उम्मीदवार ओफिर काट्ज को 52 वोट मिले। कहाना, नेतन्याहू के विरोधी गठबंधन के नेता गादी आइजेनकोट के सहयोगी हैं। 27 अक्तूबर को हुए चुनाव में नेतन्याहू और उनके सहयोगियों ने संसदीय बहुमत खो दिया था। नया स्पीकर चुने जाने से विपक्षी गठबंधन को संसद में विधायी एजेंडा आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। गठबंधन न्यायपालिका से जुड़े विवादित कानूनों को बदलने और सात अक्तूबर 2023 के हमले की जांच कराने की तैयारी में है। इस्राइल में नेतन्याहू विरोधी गठबंधन संसद में कई विवादित कानूनों को बदलने की तैयारी कर रहा है। नए स्पीकर मातान कहाना के चुनाव से विपक्ष को विधायी प्रक्रिया में बढ़त मिली है। गठबंधन प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने, न्यायपालिका की शक्तियां कमजोर करने वाले कानूनों को पलटने और सात अक्तूबर 2023 के हमले की सरकारी जांच कराने वाले प्रस्ताव लाया है। हालांकि, गठबंधन के नेता गादी आइजेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए पांच सप्ताह तक का समय है। यदि वह सरकार बनाने में नाकाम रहते हैं तो राष्ट्रपति नेतन्याहू को फिर मौका दे सकते हैं।

इटली में यहूदी-विरोधी भावना रोकने के लिए नया कानून

रोम, एजेंसी। इटली की संसद ने यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के लिए नए कानून को मंजूरी दे दी है। निचले सदन में इसे 147 वोट मिले, जबकि 93 सांसदों ने विरोध किया और पांच ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कानून में अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस एलायंस की यहूदी-विरोधी भावना की परिभाषा को शामिल किया गया है। समर्थकों का कहना है कि इससे यहूदी-विरोधी घटनाओं से निपटने में मदद मिलेगी। वहीं, आलोचकों को आशंका है कि इसका इस्तेमाल इस्राइल की नीतियों की आलोचना रोकने के लिए हो सकता है। कानून में नए अपराध या सजा का प्रावधान नहीं किया गया है।

अमेरिका में हवाई यातायात व्यवस्था पर फिर संकट

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने पिछले सप्ताह हवाई यातायात व्यवस्था में आई गड़बड़ी के बाद नए राउटर लगाने पर रोक लगा दी है। पहले से लगाए गए जुनिपर राउटर भी बंद कर दिए गए हैं। जांच में पता चला कि अर्कांसस के एल डोराडो में लगाया गया एक राउटर खराबी की वजह बना था। इससे देश के 22 में से 17 क्षेत्रीय हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र प्रभावित हुए थे। फिलहाल व्यवस्था चलाने के लिए 25 साल पुराने सिस्को राउटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

नेतन्याहू की बढ़ीं मुश्किलें: संसद में विपक्ष का बहुमत, आइजेनकोट के करीबी मतान कहाना बने नए स्पीकर

यरूशलेम, एजेंसी। इस्राइल की संसद (नेसेट) ने मंगलवार को नए स्पीकर का चुनाव किया। इसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली निवर्तमान सरकार की नीतियों को पलटने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। नए स्पीकर के रूप में मतान कहाना को चुना गया है, जो गादी आइजेनकोट के करीबी सहयोगी हैं। आइजेनकोट फिलहाल नेतन्याहू की जगह नई सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके गठबंधन ने कहाना के चुनाव के बाद नेतन्याहू की कुछ सबसे विवादित नीतियों को वापस लेने का वादा किया है।

कहाना को कितने वोट मिले : 120 सदस्यीय संसद में कहाना को 66 वोट मिले। उन्हें यह समर्थन यहूदी नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के साथ-साथ अरब नेतृत्व वाले दलों से भी मिला। वहीं, नेतन्याहू के गठबंधन की ओर से समर्थित उम्मीदवार ओफिर काट्ज को 52 वोट मिले। स्पीकर के चुनाव को लेकर संसद में सात घंटे से अधिक समय तक तीखी बहस चली। मतदान से पहले आइजेनकोट ने कहा, 'मतान कहाना की नेसेट स्पीकर के रूप में नियुक्ति एक उचित लोकतांत्रिक कदम है। यह बदलाव के पक्ष में स्पष्ट बहुमत को दर्शाती है।'

यह चुनाव 27 अक्तूबर को हुए संसदीय चुनावों के कुछ सप्ताह बाद हुआ है। इन चुनावों में नेतन्याहू और उनके सहयोगियों ने संसद में अपना बहुमत खो दिया था। इसके बाद इस्राइल के राष्ट्रपति ने आइजेनकोट



को नई गठबंधन सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी।

आइजेनकोट के पास कितना समय : आइजेनकोट के पास गठबंधन बनाने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने के लिए अधिकतम पांच सप्ताह का समय और है। सरकार गठन को लेकर बातचीत जारी रहने के बीच उनका गुट और असंबद्ध अरब नेतृत्व वाले दल नवगठित संसद में अपने बहुमत का इस्तेमाल विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। पिछले सप्ताह इन दलों ने कई विधेयक पेश किए थे। इनमें प्रधानमंत्री के पद पर कार्यकाल की सीमा तय करना, सात अक्तूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमलों की जांच के लिए सरकार के नेतृत्व में जांच आयोग गठित करना और न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने वाले कानूनों को वापस लेना शामिल है।

स्पीकर के पास संसद का एजेंडा तय करने की अहम भूमिका : यरुशलम स्थित थिंक टैंक इस्राइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के असाफ शापिरा के मुताबिक, कहाना के स्पीकर बनने से विपक्षी गठबंधन को विधायी प्रक्रिया में बड़ा फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय बहुत कम है। नेसेट का स्पीकर विधायी प्रक्रिया को बहुत तेज या बहुत धीमा कर सकता है। कहाना ने नेतन्याहू के सहयोगी अमीर ओहाना की जगह ली है। आइजेनकोट और उनके सहयोगियों पर आने वाले सप्ताहों में अपनी विधायी प्राथमिकताओं को तेजी से आगे बढ़ाने का दबाव है।

फिलहाल आइजेनकोट की याशर पार्टी के सदस्य रॉय फोकमैन अस्थायी समिति के प्रमुख हैं। सरकार बनने तक संसद के ज्यादातर कामकाज से जुड़े फैसले यही समिति करती है। अगर आइजेनकोट सरकार बनाने में नाकाम रहते हैं, तो इस्राइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू को सरकार बनाने का एक और मौका दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को समिति का नियंत्रण मिलने की संभावना है।

शापिरा ने कहा कि भले ही नेतन्याहू के विरोधियों के पास तब भी संसद में बहुमत बना रहे, लेकिन उन्हें लगेगा कि उनकी राजनीतिक गति धीमी पड़ गई है। इससे कुछ विधेयकों के अटकने का वास्तविक खतरा पैदा हो सकता है।

संसद में सात अक्तूबर के हमले को लेकर तीखी बहस : मंगलवार को संसद में हुई बहस के दौरान सात अक्तूबर के हमले के जख्म भी सामने आए। बहस शुरू होने के कई घंटे बाद लिकुड पार्टी की सदस्य तालिक ग्विली ने अरब ज्वाइंट लिस्ट के वरिष्ठ सदस्य अहमद तिबी के भाषण के बीच हस्तक्षेप किया।

ग्विली का बेटा पुलिस अधिकारी था, जिसकी सात अक्तूबर को फलस्तीनी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उस समय तिबी संसद में दक्षिणपंथी सांसदों की नस्लवादी टिप्पणियों की आलोचना कर रहे थे। इसी दौरान ग्विली ने चिल्लाते हुए पूछा, 'मेरे बेटे को किसने मारा?' इस पर तिबी ने जवाब दिया, 'आप मुझे इसके लिए जिम्मेदार क्यों ठहराने लगी हैं? किसी अरब सांसद से ऐसा सवाल मत पूछिए।' इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। संसद के आसन से तिबी ने ग्विली से बिना किसी आधार के आरोप लगाने से बचने को कहा।

न्यूयॉर्क मेयर ममदानी बोले- हिंदू-सिखों के खिलाफ नफरत बढ़ी

न्यूयॉर्क, एजेंसी। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने अमेरिका में हिंदू और सिख समुदाय के खिलाफ बढ़ती नफरत पर चिंता जताई है। ममदानी ने मंगलवार को अपने कार्यालय में दिवाली कार्यक्रम के दौरान कहा कि पिछले एक साल में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया और सिख समुदाय के खिलाफ भी नफरत फैलाई गई। रामायण और महाभारत का जिक्र करते हुए ममदानी ने कहा कि रामायण हमें सिखाती है कि हमें कैसा भाई, पति, पत्नी और दोस्त बनना चाहिए। महाभारत परिवारों की असली तस्वीर दिखाती है। ममदानी की मां मीरा नायर पंजाबी हिंदू परिवार से आती हैं। 35 साल के ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय-अमेरिकी मेयर हैं।

वॉशिंगटन हो या दिल्ली, नफरत फैलाने वाली राजनीति को रोकना होगा : ममदानी ने अमेरिका और भारत की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों की जिम्मेदारी है कि वे समाज में डर और नफरत फैलाने वाली बातों का विरोध करें। उन्होंने कहा, चाहे वॉशिंगटन हो या दिल्ली, हमें ऐसी राजनीति को खारिज करना चाहिए जो हमारी जिंदगी में अंधेरा लाती है। उन्होंने यह भी बताया कि बचपन से ही वह अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते आए हैं। अब न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर पूरे शहर के लोगों के साथ यह त्योहार मनाना उनके लिए सम्मान की बात है।

हिंदू समुदाय के खिलाफ दो घटनाएं हुईं : इलिनॉय के मंदिर में गोलीबारी की कोशिश: 11 अक्टूबर को अमेरिका के इलिनॉय राज्य के औरोरा शहर में एक हिंदू मंदिर पर गोलीबारी की कोशिश हुई थी। पुलिस के मुताबिक 19 साल का एलेक्जेंड्रोस पापोराकिस हथियार और गोलियां लेकर मंदिर पहुंचा था। उस समय मंदिर में नवरात्रि मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आरोपी की राइफल जाम हो गई थी, जिसके बाद वह वहां से चला गया। उसके एक साथी कर्मचारी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में उसके घर से राइफल, 300 से ज्यादा गोलियां और नाजी विचारधारा से जुड़ी चीजें मिलीं। आरोपी पर आतंकवादी धमकी देने और अवैध हथियार रखने के आरोप लगे हैं।

सिएटल में दिवाली कार्यक्रम में हंगामा: 7 नवंबर 2026 को अमेरिका के सिएटल में दिवाली कार्यक्रम के दौरान दो लोगों ने ने हंगामा किया। दोनों विवादित पोस्टर लेकर कार्यक्रम में घुस आए। पोस्टर पर लिखा था- 'सभी भारतीयों को देश से निकालो'। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सांसद प्रमिला जयपाल ने इसकी निंदा की। 17 नवंबर को 13 अमेरिकी सांसदों ने FBI से मामले की जांच संभावित हेट क्राइम के तौर पर करने की मांग की। गुरुद्वारे की दीवारों पर नफरत भरी बातें लिखीं: 27 दिसंबर 2025 को न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में बाबा माखन शाह लुबाना सिख सेंटर की दीवारों पर अज्ञात लोगों ने आपत्तिजनक बातें लिख दीं।

कुवैत में ड्रोन हमलों का अलर्ट, सेना ने एक्टिवेट किया एयर डिफेंस सिस्टम

कुवैत सिटी, एजेंसी। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरानी मीडिया ने किया विस्फोटों का दावा कुवैत सिटी। मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक व सैन्य तनाव के बीच कुवैत में ड्रोन हमलों का हाई अलर्ट जारी किया गया है। कुवैती सेना ने बुधवार को पुष्टि की कि देश की हवाई रक्षा प्रणालियां सक्रिय रूप से शत्रुतापूर्ण ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रही हैं। सेना के जनरल स्टाफ ने स्पष्ट किया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में सुनाई दे रही तेज धमाकों की आवाजें इन हवाई हमलों को हवा में ही रोकने (इंटरसेप्ट करने) की कार्रवाई का नतीजा हैं। कुवैती आर्मी ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान, ईरानी मीडिया ने दी विस्फोटों की खबरहवाई हमलों को नाकाम करने में जुटी सेनाः कुवैत आर्मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, 'कुवैत की हवाई रक्षा प्रणालियां इस समय शत्रुतापूर्ण ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रही हैं।' जनरल स्टाफ के अनुसार, एयर डिफेंस यूनिट्स पूरी सतर्कता के साथ हवाई खतरों को निष्क्रिय करने में जुटी हुई हैं, जिससे आसमान में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं।

अरब सूत्रों के हवाले से विस्फोटों का दावा: दूसरी ओर, बीबीसी फारसी से मिली जानकारी के अनुसार, ईरानी मीडिया ने 'अरब सूत्रों' के हवाले से कुवैत में कई विस्फोट होने की खबरें प्रसारित की हैं। खाड़ी क्षेत्र में गहराता सैन्य टकराव, ईरान ने दी है अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी

बहरीन के बाद अब कुवैत में हलचलः गौरतलब है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच सीधा तनाव चरम पर है। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने बहरीन स्थित अमेरिकी रडार ठिकानों पर हमले करने की घोषणा की थी। तेहरान ने इसे केशम और सिरिक सहित खाड़ी के तटीय इलाकों में हुए अमेरिकी हवाई हमलों की जवाबी कार्रवाई करार दिया था।

अमेरिका: 83 महिला सांसदों की अश्लील डीपफेक तस्वीरें ऑनलाइन? पेरिस हिल्टन के खुलासे से मचा हड़कंप

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और बिना सहमति के बनाई गई अश्लील तस्वीरों (अश्लील डीपफेक) का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। मॉडल और रियलिटी टीवी स्टार पेरिस हिल्टन ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए दावा किया है कि अमेरिकी कांग्रेस की 156 महिला सांसदों में से 83 की अश्लील डीपफेक तस्वीरें फिलहाल इंटरनेट पर मौजूद हैं। हिल्टन ने मंगलवार शाम सीएनएन के कार्यक्रम 'द लीड' में एंकर जेक टैपर से बातचीत के दौरान यह जानकारी साझा की। उनका यह खुलासा सुनकर टैपर भी हैरान रह गए।

हिल्टन इन दिनों अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) से डीईएफआईएएनसीई एक्ट पारित कराने की मांग कर रही हैं। यह



विधेयक इंटरनेट पर बिना सहमति के बनाई और साझा की जाने वाली यौन तस्वीरों और डीपफेक सामग्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। मंगलवार को उन्होंने इस कानून को पारित कराने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नेतृत्व से मुलाकात भी की। हिल्टन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जनवरी में कांग्रेस में डेमोक्रेटिक बहुमत आने से पहले मौजूदा सत्र में ही यह विधेयक पारित हो जाएगा। इससे पहले यह विधेयक अमेरिकी सीनेट से पारित हो चुका है।

विधेयक पारित नहीं हुआ तो पीड़ितों के लिए होगा दुखद : सीएनएन के एंकर जेक टैपर ने जब हिल्टन से पूछा कि क्या इस विधेयक को प्रतिनिधि सभा में पर्याप्त समर्थन मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का मौजूदा सत्र समाप्त होने से पहले इसे पारित नहीं किया गया, तो यह पीड़ितों के लिए बेहद दुखद होगा। हिल्टन ने इस मुद्दे को किसी राजनीतिक दल से जुड़ा मामला मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा, 'यह रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी का मुद्दा नहीं है।' उनके मुताबिक, ऑनलाइन यौन डीपफेक एक महामारी की तरह फैल रहे हैं और इससे निपटने के लिए कई स्तरों पर प्रयास करने की जरूरत है। हिल्टन ने प्रतिनिधि सभा की सांसद अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज (डेमोक्रेट-न्यूयॉर्क) और लॉरेल ली (रिपब्लिकन-फ्लोरिडा) की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों सांसदों ने इस विधेयक पर उनके साथ काम किया है और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने इस विषय पर एक अध्ययन किया है। इसके मुताबिक, अमेरिकी कांग्रेस की कुल 156 महिला सांसदों में से 83 की यौन डीपफेक तस्वीरें इस समय ऑनलाइन मौजूद हैं। हिल्टन ने कहा कि यह समस्या सभी को प्रभावित कर रही है। यह आंकड़ा सुनकर जेक टैपर ने हैरानी जताते हुए कहा, 'यह वाकई भयावह है।' डीईएफआईएएनसीई एक्ट का उद्देश्य बिना सहमति के किसी व्यक्ति की अश्लील या यौन तस्वीरें बनाने और उन्हें इंटरनेट पर साझा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता मजबूत करना है।

अलास्का में भी जीते डेमोक्रेट्स: मैरी पेल्टोला ने रिपब्लिकन से छीना राज्य, 70 साल बाद सीनेट में सबसे बड़ी बढ़त

अलास्का , एजेंसी। अलास्का में अमेरिकी सीनेट की कड़े मुकाबले वाली दौड़ में, पूर्व प्रतिनिधि मैरी पेल्टोला ने रिपब्लिकन सीनेटर डैन सुलिवन को हरा दिया है। इस जीत के साथ ही, रिपब्लिकन पार्टी के कब्जे वाली एक और सीट (कुल नौवीं सीट) डेमोक्रेट्स के खाते में चली गई है। यह पिछले लगभग 70 वर्षों में किसी मध्यावधि चुनाव (मिडटर्म इलेक्शन) में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए सबसे बड़ी बढ़त है।

अलास्का के लिए यह जीत क्यों है खास : पूर्व अमेरिकी कांग्रेसवुमन पेल्टोला, अलास्का की पहली डेमोक्रेटिक सीनेटर बनेंगी। उनसे पहले मार्क बेगिच इस सीट पर थे, जो 2009 से 2015 तक इस पद पर रहे थे। बता



दें कि वह अमेरिकी सीनेट के लिए चुनी जाने वाली अलास्का की पहली मूल निवासी महिला हैं। वह उन केवल दो मूल निवासी महिलाओं में से एक हैं जो इस पद पर पहुंची हैं; दूसरी महिला पैगी फ्लैनागन हैं, जिन्होंने इस साल मिनेसोटा में सीनेट का चुनाव जीता है। अलास्का का मुकाबला मध्यावधि चुनावों में सीनेट की आखिरी दौड़ थी, जिसका परिणाम घोषित किया गया। इस मुकाबले में एक निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर विवाद भी हुआ, जिसका नाम सुलिवन के नाम से मिलता-जुलता था।

पहले क्या थे ये आंकड़े : इससे पहले, 1958 में रिपब्लिकन राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के दूसरे कार्यकाल के दौरान, डेमोक्रेट्स ने मध्यावधि चुनाव में नौ या उससे अधिक सीनेट सीटें जीती थीं। उस साल, डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी के कब्जे वाली 13 सीटें छीन ली थीं और अलास्का की दो नई बनी सीटों पर भी जीत हासिल की थी, जिससे उन्हें कुल 15 सीटों का फायदा हुआ था।

पेल्टोला की जीत के बाद, जनवरी में जब नई कांग्रेस शुरू होगी, तब डेमोक्रेट्स के पास 56-44 का बहुमत होगा। पिछले 16 वर्षों में सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी की यह सबसे बड़ी बढ़त है। 3 जनवरी 2011 को समाप्त हुई 111वीं कांग्रेस के अंतिम दिनों में, डेमोक्रेट्स के पास सीनेट की 58 सीटें थीं। अगर अलास्का की सीट को छोड़ भी दें, तब भी डेमोक्रेट्स को जनवरी 2015 के बाद से सबसे बड़ा बहुमत मिल गया है। 2014 के मध्यावधि चुनावों में, राष्ट्रपति बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल के दौरान, रिपब्लिकन पार्टी ने डेमोक्रेट्स की नौ सीटें जीतकर सत्ता पर अपना नियंत्रण बना लिया था। बुधवार को मिसिसिपी में अमेरिकी सीनेट की दौड़ में डेमोक्रेट स्कॉट कोलोम की जीत के साथ, उनकी पार्टी को रिपब्लिकन पार्टी के कब्जे वाली आठवीं सीट मिल गई।

एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सन हुआंग वापसी को तैयार:कहा- बोर्ड के फैसले पर ही लौटूंगा; चेयरमैन बोले- ऐसा कोई इरादा नहीं

कैलिफोर्निया, एजेंसी। एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सन हुआंग पद पर वापसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस्तीफे के बाद मंगलवार को पहली बार एक्स पर पोस्ट कर बयान जारी किया। हुआंग ने पिछले हफ्ते एक चीनी महिला जासूस से अफेयर की खबरों के बाद पद छोड़ा था। अपने पोस्ट में हुआंग ने लिखा, अगर बोर्ड फैसला करता है कि मेरी वापसी शेयरहोल्डर्स, कर्मचारियों, कंपनी और अमेरिका के हित में है, तो मैं उन अपीलों का जवाब देने और सीईओ के रूप में लौटने पर सम्मानित महसूस करूंगा। हालांकि, एनवीडिया के चेयरमैन ने साफ कर दिया है कि बोर्ड का जेन्सन हुआंग को फिर से सीईओ बनाने का कोई इरादा नहीं है।

इस्तीफे के बाद जेन्सन का ये बयान क्यों अहम है... ये वापसी की खुली अपील है: हुआंग ने सीधे नहीं कहा- 'मुझे वापस लो।' उन्होंने कहा- 'अगर बोर्ड चाहे तो मैं तैयार हूं।' ये एक तरह से बोर्ड पर जनता और कर्मचारियों का दबाव बनाने वाली रणनीति मानी जा रही है।

गलती मानी, लेकिन डिटेल नहीं दी: उन्होंने गंभीर गलतियां और बोर्ड के लिए समस्याएं मानीं, लेकिन किस अफेयर की बात हो रही है, इसका नाम नहीं लिया।

अमेरिका कार्ड खेला: बयान में 3 बार अमेरिका, अमेरिकी नागरिक, अमेरिका के हित में कहा। ये इसलिए, क्योंकि उन पर आरोप चीन से जुड़े हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका के साथ हैं।

परिवार से माफी: आखिरी लाइन में पत्नी और बच्चों से माफी



मांगी, 'मैं बाकी जिंदगी तुम्हारे लायक बनने में बिताऊंगा। '

हुआंग की वापसी के समर्थन में आए 1.90 लाख लोग : जेन्सन हुआंग की एनवीडिया में वापसी की मांग वाली ऑनलाइन याचिका पर 1 लाख 90 हजार से ज्यादा लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। टेक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी उनकी वापसी का समर्थन किया है।

अमेरिकी संसद की समितियों के सामने पेश होंगे हुआंग : एनवीडिया के चिप्स चीन भेजने और अमेरिकी नियमों के उल्लंघन को लेकर कंपनी की जांच चल रही है। अमेरिकी संसद की प्रमुख समितियों ने मंगलवार को बताया कि जेन्सन हुआंग जांच में अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हो गए हैं। वह 1 दिसंबर को समितियों के सामने पेश होंगे। इसके अगले दिन, 2 दिसंबर को कंपनी के जनरल काउंसल टिम टेटर से सवाल-जवाब होंगे। इस बीच, एनवीडिया ने नियमों की निगरानी के लिए बोर्ड की एक नई समिति बनाई है। यह समिति देखेगी कि कंपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे देशों को चिप्स बेचने से जुड़े अमेरिकी नियमों का पालन कर रही है।

ट्रंप को मारना चाहता था पाकिस्तानी, अमेरिका ने सुनाई 27 साल 6 महीने की सजा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाले पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को 27 साल छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है। अभियोजकों का कहना है कि यह साजिश ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के निर्देश पर रची गई थी। हालांकि, अमेरिकी जांच एजेंसियों ने समय रहते इसे नाकाम कर दिया और किसी हमले को अंजाम नहीं दिया जा सका। अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को बताया कि न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित संघीय अदालत में जिला न्यायाधीश एरिक आर. कोमिटी ने मर्चेंट को 330 महीने की सजा सुनाई। 48 वर्षीय मर्चेंट को छह मार्च को जूरी ने हत्या के लिए सुपारी देने और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से परे आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश के आरोपों में दोषी ठहराया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मर्चेंट ने एक अमेरिकी राजनीतिक नेता की हत्या के लिए पेशेवर हत्यारों की तलाश की थी। हालांकि, जिन लोगों को उसने इसके लिए पैसे दिए, वे वास्तव में एफबीआई के अंडरकवर एजेंट थे। जांच एजेंसी ने हमले से पहले ही पूरी योजना का खुलासा कर दिया। मर्चेंट ने अदालत में गवाही दी। उसका मानना था कि इस साजिश का मुख्य निशाना ट्रंप थे। अभियोजकों के मुताबिक, उस



समय के राष्ट्रपति जो बाइडेन और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली भी संभावित निशानों में शामिल थे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने सजा की घोषणा करते हुए कहा, ''न्याय विभाग हमारे नेताओं के खिलाफ विदेशी आतंकवादी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा।'' अभियोजकों का दावा था कि इस साजिश का मकसद ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना था। सुलेमानी जनवरी 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। हालांकि, मर्चेंट ने अभियोजन पक्ष के इस दावे पर सवाल उठाया था कि वह वास्तव में हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए तैयार था। उसने अदालत में कहा था कि ईरान में उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर उसे डर था और उसका इरादा कभी भी हत्या करवाने का नहीं था। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, मर्चेंट स्वेच्छा से रिवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया अभियान में शामिल हुआ था और अमेरिका आने से पहले उसे प्रशिक्षण दिया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, एक रिश्तेदार के माध्यम से उसकी पहचान ईरान में मौजूद एक हैंडलर से कराई गई थी। इसके बाद तेहरान में दोनों की कई मुलाकातें हुईं।

मर्चेंट को कथित तौर पर काउंटर इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया गया और राजनीतिक रैली के दौरान हत्या को अंजाम देने के लिए अपराधियों की भर्ती करने के निर्देश दिए गए। मर्चेंट अप्रैल 2024 में ईरान में कुछ समय बिताने के बाद अमेरिका पहुंचा। उसने इस योजना में मदद के लिए अपने एक परिचित से संपर्क किया, लेकिन उस व्यक्ति ने एफबीआई को इसकी जानकारी दे दी और जांच एजेंसी के लिए मुखबिर बन गया। मुकदमे के दौरान पेश की गई एक रिकॉर्डिंग में मर्चेंट को कथित तौर पर यह समझाते हुए सुना गया कि किसी राजनीतिक नेता की रैली के दौरान हत्या किस तरह की जा सकती है। बाद में उसने उन लोगों से मुलाकात की, जिन्हें वह सुपारी लेकर हत्या करने वाले पेशेवर अपराधी समझ रहा था। उसने उन्हें बताया कि वह विदेश में मौजूद कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, प्रस्तावित गतिविधियों में दस्तावेजों की चोरी, राजनीतिक रैलियों में विरोध प्रदर्शन आयोजित करना और एक राजनीतिक नेता की हत्या करना शामिल था।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

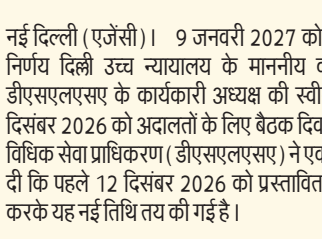
Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दिल्ली में महिला इन्फ्लुएंसर के घर में घुसने पर पिटाई के बाद चेन्नई के व्यक्ति की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक महिला 'इन्फ्लुएंसर' से मिलने के लिए चेन्नई से आए एक व्यक्ति की महिला के घर में घुसने पर उसके परिजनों और पड़ोसियों द्वारा की गई कथित पिटाई के बाद मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि यह घटना सात नवंबर को हुई, जब चेन्नई की एक निजी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति कथित तौर पर महिला के घर में घुस गया, जिसके बाद उसके परिजनों और पड़ोसियों के साथ विवाद हो गया और उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। इस मामले में महिला के पिता और एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है। जांच के अनुसार, चेन्नई निवासी यह व्यक्ति सोशल मीडिया पर महिला के संपर्क में आया था और नियमित रूप से उसके वीडियो लाइक करता था। पुलिस का कहना है कि वह महिला से एक तरफा प्यार करने लगा और उससे मिलने के लिए चेन्नई से दिल्ली आ गया। विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर महिला के 29 लाख से अधिक 'सब्सक्राइबर' हैं। एक पुलिस सूत्र ने कहा, ''सात नवंबर को वह घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिससे विवाद शुरू हो गया। महिला के पिता और कुछ पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी और बाहरी चोटें आईं।' सूत्र ने बताया कि घायल व्यक्ति को पहले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया। हालत में सुधार न होने पर उसे बाद में एक अन्य अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद, मधु विहार पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और महिला के पिता व एक पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान महिला के भाई और अन्य पड़ोसियों की भूमिका भी सामने आई है। शेष संदिग्धों की पहचान करने और हमले में उनकी भूमिका तय करने के लिए पुलिस की टीमें घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही हैं।

दिल्ली : कश्मीरी गेट इलाके में फॉर्च्यूनर ने मारी टक्कर, दो लोगों की मौत, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में 17 और 18 नवंबर की दरमियानी रात एक तेज रफ्तार सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी की टक्कर से घायल हुए दो युवकों की मौत हो गई। फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने आरोपी फॉर्च्यूनर चालक के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र में युधिष्ठिर सेतु पर 17 और 18 नवंबर की दरमियानी रात एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर और टीएसआर (ऑटो) के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में कुल 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दो लोगों की हालत गंभीर होने पर उनका उपचार शुरू किया गया था। उधर, पुलिस ने मामले में शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 और 125ए के तहत एफआईआर दर्ज की। हालांकि, हादसे में घायल हुए दो लोगों ने बुधवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले में दर्ज एफआईआर में बीएनएस की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) जोड़ी है। मृतकों की पहचान के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने आनी बाकी है। फिलहाल पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुटी है और उसे पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उधर, उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम इस मामले में आगे की जांच में जुटी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 8 बजे व्यक्ति का शव भजनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गमरी गांव में मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दी। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच पड़तालर की। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।



लोन दिलाने के नाम पर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश

नई दिल्ली (एजेंसी)। रोहिणी जिले के विजय विहार इलाके में सस्ते और जीरो ब्याज दर पर लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास छापेमारी कर कॉल सेंटर के मैनेजर और एक महिला टीम लीडर समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर इनके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि विजय विहार फेज-2 निवासी विकास की शिकायत पर 17 नवंबर को मामला दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि यह गिरोह एक कॉर्पोरेट दफ्तर की तरह काम करता था, जिसमें बकायदा फ्लोर मैनेजर, टीम लीडर और टेली-कॉलर रखे गए थे। आरोपियों में शाहदरा निवासी एक महिला टीम लीडर, रघुबीर नगर निवासी कॉल सेंटर का मैनेजर जतिन व चार टेलीकॉलर उत्तम नगर निवासी नीरज,द्वारका निवासी आकाश, विकास नगर निवासी सनी और वजीरपुर निवासी दया प्रसाद शामिल हैं।

दिल्ली में 9 जनवरी को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

नई दिल्ली (एजेंसी)। 9 जनवरी 2027 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और डीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष की स्वीकृति से लिया गया है, क्योंकि 12 दिसंबर 2026 को अदालतों के लिए बैठक दिवस घोषित किया गया है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने एक अधिसूचना जारी करके जानकारी दी कि पहले 12 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित करके यह नई तिथि तय की गई है।

पार्क में खुले सीवर में गिरकर दो बच्चों की मौत के लिए डीडीए व डीजेबी जिम्मेदार : हाई कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीतमपुरा के एक पब्लिक पार्क में खुले सीवर में गिरकर दो बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को लापरवाही का दोषी ठहराया है। मृतक बच्चों के माता-पिता की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि डीडीए-डीजेबी ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं और दुर्घटना रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती।

'उपाय नाकाफी थे'

पीठ ने कहा कि दो बच्चों का खुले सीवर में गिरकर जान गंवाना बताता है कि सुरक्षा उपाय नाकाफी थे। उक्त टिप्पणियों के साथ पीठ ने इसके साथ ही डीडीए व डीजेबी को प्रत्येक पीड़ित परिवार को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 11.01 लाख रुपये मुआवजा व एक लाख रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया। 16 अप्रैल 2010 को करीब साढ़े ग्यारह साल के रोबियाल और लगभग 12 साल के अर्जुन की पीतमपुरा में डबल टंकी के पास डीडीए पार्क के एसयू-ब्लाक में खुले सीवर/मैनहोल में गिरने से मौत हो गई थी। बच्चों के माता-पिता ने पार्क और सीवर के काम के लिए जिम्मेदार डीडीए व डीजेबी से मुआवजे की मांग की थी।

अब रेस्टोरेंट वाले बिल में मनमर्जी से नहीं वसूल सकेंगे सर्विस चार्ज, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट को ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति देने वाली कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे व न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने कहा कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन को 28 मार्च 2025 के फैसले के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा नहीं मिली है।

एकल पीठ के फैसले को रखा बरकरार-उक्त निर्णय में एकल पीठ ने सर्विस चार्ज पर रोक लगाने वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशानिर्देश को बरकरार रखा था।

दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अभिनेता जैकी श्रॉफ ने छठ घाट की सफाई अभियान में हिस्सा लिया

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ बृहस्पतिवार को उत्तर दिल्ली में मुनक नहर छठ घाट पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'स्वच्छता संकल्प' के तहत सभी को अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए।
गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा, 'जब हम त्योहार मनाते हैं और अपनी संस्कृति व परंपराओं को भव्यता से निभाते हैं, तो हर आयोजन के बाद अपने आसपास के क्षेत्रों और शहर को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यह केवल मुनक नहर की बात नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली की बात है।'
उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम करेगी, लेकिन लोगों को भी एक साथ आकर राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ रखना चाहिए।
इस साल, दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के एक सूखे हिस्से के किनारे 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट बनाया था। इस कार्यक्रम का आयोजन भामला फाउंडेशन और मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा किया गया था।



दिल्ली की पांचों भाषा अकादमियों की शासी परिषद का पुनर्गठन, सीएम रेखा गुप्ता ने दी बधाई

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग ने हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मैथिली-भोजपुरी और गढ़वाली, कुमाऊंनी एवं जौनसारी अकादमी की शासी परिषदों का पुनर्गठन कर दिया है।
सभी अकादमियों के लिए 18 नवंबर को अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गईं, जिनमें पूर्व अधिसूचनाओं को निरस्त कर नई परिषदों का गठन किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए सभी नवनियुक्त उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, ÷दिल्ली केवल देश की राजधानी नहीं, बल्कि भारत की विविध भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों का जीवंत संगम है। आप सभी के नेतृत्व में दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान और समृद्ध होगी, हमारी गौरवशाली विरासत को नया विस्तार मिलेगा और युवा पीढ़ी का अपनी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव और मजबूत होगा।÷
उन्होंने सभी को सफल एवं यशस्वी कार्यकाल की मंगलकामनाएं दीं। हिंदी अकादमी की शासी परिषद में मंत्री (कला, संस्कृति एवं भाषा) अध्यक्ष होंगे, जबकि अनिल अग्रवंशी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। परिषद में गजेंद्र सोलंकी, रितु गोयल, भुवनेश सिंघल, प्रवीण आर्य, रितु दुबे तिवारी, प्रो. कृष्णा शर्मा, प्रो. ममता वालिया, सोनाली मिश्रा, जय सिंह आर्य, मनोज शर्मा, जितेंद्र वीर कालरा, मुकेश अग्रवाल, डॉ. कीर्ति काले, डॉ. नवीन गुप्ता और अनंत विजय को सदस्य बनाया गया है। संस्कृत अकादमी में प्रो. यशवीर सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। परिषद में पं. गिरधारी लाल, संजय शर्मा, रेनू अग्रवाल, हर्षित उपाध्याय, डॉ. दुर्गेश मिश्रा, कौशल किशोर तिवारी, प्रो. सुधीर कुमार आर्य, प्रो. रंजीत बेहरा, प्रो. जयप्रकाश नारायण, डॉ. जीवन शर्मा, आचार्य सुधीर शर्मा, डॉ. अमोल मणि मिश्रा और डॉ. सुशील कुमार सदस्य होंगे। पंजाबी अकादमी के उपाध्यक्ष सरदार इमप्रीत सिंह बख्शी होंगे। इसमें डॉ. जसविंदर कौर बिंद्रा, सरदार बलबीर सिंह, डॉ. गुरमीत सिंह सुरा, जैसमीन सिंह नाउनी, के.एस. दुग्गल, हरीश हरजाई, गुरमीत कोहली, हरजेंद्र सोढी, संकेश सिद्धू, अवतार साहनी, सरदार कुलवंत सिंह बाठ, सचिन भसीन, राजीव गुगलानी, सुमित सेठ, शशि जेटली, सरदार जगदीश सिंह, सरदार चरणजीत सिंह लवली, सरदार इसप्रीत सिंह और सरदारनी सतबीर कौर शामिल हैं।

दिल्ली-एनसीआर रोबोटिक हार्ट सर्जरी में बना देश का सबसे बड़ा केंद्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से होने वाली हार्ट सर्जरी के मामले में दिल्ली-एनसीआर देश का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में रोबोटिक हार्ट सर्जरी का तेजी से विस्तार हो रहा है। माना जा रहा कि यही रफ्तार रही तो 2031 तक भारत कम चीरा लगाकर की जाने वाली हार्ट बाईपास सर्जरी के मामले में कई बड़े देशों को भी पीछे छोड़ सकता है। यह चर्चा सोसाइटी ऑफ मिनिमली इनवेसिव कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन्स ऑफ इंडिया के 10वें वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर हुई। तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित होगा। इसमें 30 से अधिक देशों के करीब 1,200 डॉक्टरों, विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल रोबोटिक हार्ट सर्जरी के 21 सिस्टम मौजूद हैं। 2025 में यहां करीब 1,800 रोबोटिक हार्ट सर्जरी की गई, जो देश के दूसरे प्रमुख शहरों से अधिक हैं। इस मामले में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। 2026 में रोबोटिक हार्ट सर्जरी की संख्या में करीब 40 प्रतिशत बढ़ोतरी होने का अनुमान है। फिलहाल देश में मौजूद इन रोबोटिक सिस्टम में 87 प्रतिशत निजी और 13 प्रतिशत सरकारी अस्पतालों में हैं। सम्मेलन की आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. युगल के मिश्रा ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में बेहतर अस्पतालों, आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टरों की उपलब्धता के कारण रोबोटिक हार्ट सर्जरी तेजी से बढ़ रही है। इस तकनीक से डॉक्टर छोटे चीरे लगाकर जटिल ऑपरेशन कर सकते हैं। इससे मरीज को कम दर्द होता है और वह पारंपरिक सर्जरी की तुलना में जल्दी ठीक होकर सामान्य जीवन में लौट सकता है।

डीटीसी बेड़े में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें होगी शामिल, दिल्ली-हापुड़ बस सेवा होगी शुरू

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में 100 नई शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही है। इन बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली में बसों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 7,088 हो जाएगी, जिसमें 5,338 इलेक्ट्रिक और 1,750 सीएनजी बसें शामिल होंगी। इसके साथ ही दिल्ली देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाले शहर के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगी।
उन्होंने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इन 100 नई इलेक्ट्रिक बसों में 50 नौ मीटर और 50 बारह मीटर लंबाई वाली बसें शामिल होंगी। सुरक्षित, आरामदायक और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार ये लो-फ्लोर, वातानुकूलित बसें सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम और दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाओं सहित आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस होंगी।
मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल करना दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम और स्वच्छ मोबिलिटी समाधानों के माध्यम से बदलने की दिल्ली सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के बस बेड़े का व्यापक और चरणबद्ध विस्तार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2028-29 तक दिल्ली में बसों की कुल संख्या लगभग 14,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर आधारित यह विस्तार सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी को मजबूत करने, बस सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने और स्वच्छ एवं टिकाऊ शहरी परिवहन के दीर्घकालिक विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मंत्री बताया कि इलेक्ट्रिक बस बेड़े के विस्तार के साथ-साथ दिल्ली सरकार आनंद विहार आईएसबीटी और उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने जा रही है। प्रस्तावित सेवा से दिल्ली, गाजियाबाद और हापुड़ के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को निर्धारित समय-सारिणी वाली, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। इस व्यवस्था के तहत डीटीसी द्वारा आनंद विहार आईएसबीटी-हापुड़ मार्ग पर 12 पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय बस सेवा के तहत आनंद विहार आईएसबीटी से बसें सुबह 5:15 बजे से 8:55 बजे तक तथा इसके बाद सुबह 11:55 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक उपलब्ध होंगी। दोनों समयावधियों में बसों का संचालन 20 मिनट के अंतराल पर किया जाएगा। वापसी में हापुड़ से बसें सुबह 8:05 बजे से 11:45 बजे तक तथा इसके बाद दोपहर 2:45 बजे से शाम 6:25 बजे तक 20 मिनट के अंतराल पर संचालित होंगी।
इस मार्ग पर आनंद विहार आईएसबीटी से हापुड़ बस स्टेशन तक बसें घड़ौली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर, डाबर, मोहन नगर, न्यू बस स्टैंड गाजियाबाद, ओल्ड गाजियाबाद बस स्टैंड, हापुड़ चुंगी, आईएमएस कॉलेज गाजियाबाद (डासना), मसूरी, छिजारसी-कुलीच नगर, पिलखुवा और निजामपुर सहित प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेंगी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के महत्व पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि डीटीसी की अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का विस्तार दिल्ली की सीमाओं से बाहर भी यात्रियों को सुगम और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित आनंद विहार-हापुड़ बस सेवा से विशेष रूप से दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, कामकाजी पेशेवरों और दिल्ली, गाजियाबाद तथा हापुड़ के बीच आवागमन करने वाले अन्य यात्रियों को लाभ मिलेगा। मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अंतरराज्यीय मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि टिकाऊ परिवहन व्यवस्था प्रभावी, सुलभ और यात्रियों की जरूरतों के अनुरूप भी हो।

हरी नगर के गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश

नई दिल्ली (एजेंसी)। साहिबपुरा, तिलक नगर के बाद अब हरी नगर स्थित गुरुद्वारा साहिब में भी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश का मामला सामने आया है। गुरुद्वारों में बेअदबी की लगातार सामने आ रहीं घटनाओं को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चिंता जताई है। कमेटी ने इसे गहरी साजिश की आशंका बताते हुए पुलिस से विस्तृत जांच कराने और आरोपियों को बेनकाब करने की मांग की है। कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि तीन दिन पहले साहिबपुरा के गुरुद्वारे में घटना हुई थी और अब हरी नगर में भी ऐसी कोशिश की गई। हालांकि, गुरुद्वारे के प्रबंधकों और संगत की सतर्कता से इस प्रयास को विफल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं को सामान्य रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इनके पीछे क्या कारण हैं और कौन लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि इन घटनाओं के जरिए सिख कौम में बेचैनी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। कालका और काहलों ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिशें मानवता के खिलाफ हैं और इनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। कमेटी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और वास्तविक दोषियों को सामने लाने की मांग करेगी।

इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती पर गुरुवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पार्टी नेताओं ने शक्ति स्थल पहुंचकर भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनिल भारद्वाज ने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने स्वतंत्र भारत में देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत की भूमिका और 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण उनके कार्यकाल के प्रमुख फैसलों में शामिल रहे।भारद्वाज ने कहा कि इंदिरा गांधी ने गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं। दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों और पुनर्वास कॉलोनियों को बसाने में भी उनकी भूमिका रही।

दिल्ली में 40 लाख से अधिक इमारतों के प्रारंभिक सुरक्षा सर्वेक्षण में लगेंगे 40 लाख कार्यघंटे-एमसीडी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 40 लाख से अधिक इमारतों का प्रारंभिक सुरक्षा सर्वेक्षण करने में करीब 40 लाख कार्य घंटे लगने का अनुमान है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कवायद में संपत्ति कर और पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग (डीईएमएस) सहित अन्य विभागों की मदद ली जाएगी, ताकि इमारतों से जुड़ी जानकारियां जुटाकर उनका एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा सके। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद नगर निगम ने एक सप्ताह से अधिक समय पहले दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में प्रस्तावित शहरव्यापी सर्वेक्षण के लिए आवश्यक श्रमशक्ति, संसाधनों और समय का विवरण दिया गया था। अधिकारी ने कहा, ''इस कवायद के लिए विस्तृत प्रश्नावली तैयार करने के वास्ते हम संपत्ति कर और सफाई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसका उद्देश्य इमारतों से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां जुटाना और उनकी संरचनात्मक सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा के आकलन के लिए एक समान मानदंड तय करना है।'' उन्होंने कहा कि इस प्रश्नावली में इमारतों कितनी पुरानी है, निर्मित क्षेत्रफल, मंजिलों की संख्या, स्वीकृत भवन योजनाएं, अग्नि सुरक्षा मंजूरी और ढांचागत कमजोरी के प्रत्यक्ष संकेतों (जैसे दरारें या झुकी हुई दीवारें) के साथ-साथ स्वच्छता से जुड़े पहलुओं जैसे कचरा प्रबंधन, जल निकासी और आसपास के इलाकों की स्थिति को शामिल किए जाने की उम्मीद है।

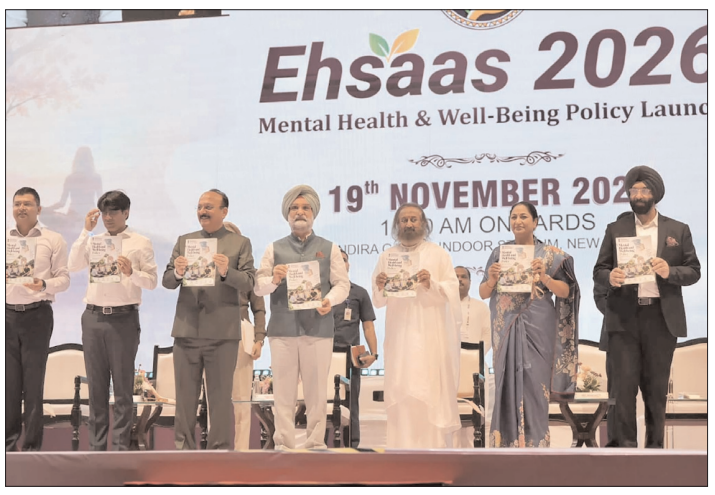
दिल्ली : लाजपत नगर में चार मंजिला इमारत में आग लगने से एक कर्मचारी की मौत, दूसरा घायल

नई दिल्ली, एजेंसी।
दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर-दो इलाके में चार मंजिला इमारत के बेसमेंट में आग लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य झुलस गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार दोपहर करीब एक बजकर 17 मिनट पर हुई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर इमारत में मौजूद लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।
पुलिस ने बताया कि बेसमेंट से गौरव नामक कर्मचारी को निकाल कर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, प्रेम सिंह शर्मा आग में झुलस गया और उसे अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में भर्ती किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, चार मंजिला इमारत के बेसमेंट में इमारत के मालिक द्वारा संचालित मीडिया हाउस है, जबकि ऊपरी मंजिलों पर मालिक के रिश्तेदार और अन्य लोग रहते हैं।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटना के समय बेसमेंट में संभवत: अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने के सिलसिले में वेल्डिंग का काम किया जा रहा था। इस दौरान दो कर्मचारी वेल्डिंग का काम कर रहे थे और इमारत के दोनों कर्मचारी भी वहां मौजूद थे।
पुलिस ने बताया कि अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार को भी पूछताछ और सत्यापन के लिए बुलाया गया है।
पुलिस ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और घटना के सटीक कारण का अभी पता नहीं चला है।
अधिकारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इमारत के मालिक, ठेकेदार तथा संबंधित श्रमिकों की भूमिका की जांच की जा रही है।



दिल्ली सरकार ने बच्चों, युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य नीति पेश की

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को अपनी मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति पेश की, जिसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं के भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह नीति छात्रों के लिए भावनात्मक सहयोग को लेकर जताई गई चिंताओं के मद्देनजर तैयार की गई है।
नीति की शुरुआत के मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद थे।
सूद ने कहा कि कुछ दिन पहले एक स्कूली छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर गया और उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर एक व्यापक नीति बनाने की दिशा में काम करने के लिए उनके तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा की।
सूद ने कहा कि बच्चे अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि माता-पिता परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए काम में व्यस्त रहते हैं।
उन्होंने कहा कि बच्चे अपने भविष्य, अकादमिक प्रदर्शन और बेहतर करने की अभिभावकों की उम्मीदों को लेकर दबाव का सामना करते हैं।
सूद ने कहा, 'लोग अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को एक वर्जित विषय मानते हैं। इसी के मद्देनजर हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि समाज में संदेश दिया जा सके कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना और इसे लेकर जागरूकता फैलाना जरूरी है।'
उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य एक ऐसा माहौल बनाना है, जहां बच्चे अपनी भावनात्मक भलाई के बारे में खुलकर बात कर सकें और बिना किसी झिझक के मदद मांग सकें।
सूद के मुताबिक, यह नीति सीएम श्री स्कूल, सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान और दिव्यांग बच्चों से जुड़े संस्थानों में लागू होगी।
उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य 29 साल तक के युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाना है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं।
सूद के अनुसार, नीति में शिक्षण, गैर-शिक्षण और परिवहन कर्मचारियों के लिए मनोमितीय आकलन की भी परिकल्पना की गई है, जो नियमित रूप से बच्चों के साथ बातचीत करते हैं।



उन्होंने बताया कि नीति के तहत ऐसी पुस्तिकाएं भी तैयार की जाएंगी, जिनमें व्यवस्थित प्रश्न, अभ्यास और गतिविधियां शामिल होंगी, ताकि कर्मचारी बच्चों के साथ संवेदनशीलता और समझदारी से संवाद कर सकें।